घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 276- गुरूवार 06- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

आरबीआई अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से जारी करेगा प्लास्टिक के नोट : मल्होत्रा

मुंबई,05 अगस्त 2026। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2027-28 की शुरुआत में पॉलिमर यानी प्लास्टिक के नोट जारी करने की तैयारी कर रहा है। ये नोट खासतौर पर कम मूल्य वर्ग के नोटों के लिए उपयोगी होंगे,क्योंकि इनका उपयोग और चलन अधिक होता है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद यहां प्रेस कांफ्रेंस को सबोधित करते कहा कि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027-28 की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट जारी करना है, बशर्ते अभी चल रहे फील्ड ट्रायल सफल हों। मल्होत्रा ने कहा कि कुछ देशों में पॉलिमर नोट का 30 साल से अधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा कि अगर सभी योजनाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती हैं तो हमारा लक्ष्य है कि ये नोट अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में चलन में आ जाएं। आरबीआई गवर्नर के अनुसार पॉलिमर नोटों के लिए जरूरी विशेष सामग्री की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इसके बाद गुणवत्ता परीक्षण,सुरक्षा मानकों की जांच और विभिन्न तकनीकी स्वीकृतियां ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में कई स्तर के परीक्षण और अत्याधुनिक सुरक्षा फीचर शामिल होंगे। संजय मल्होत्रा ने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही इन नोटों को बाजार में उतारा जाएगा। यदि योजना के मुताबिक काम आगे बढ़ा, तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में इन नोटों को आम जनता के लिए जारी किया जा सकता है।

बिना इंश्योरेंस गाड़ी को नहीं मिलेगा पेट्रोल! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सुझाव,थर्ड-पार्टी बीमा अवधि भी बढ़ाई

नई दिल्ली,05 अगस्त 2026। यदि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलना मुश्किल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिना बीमा वाले वाहनों पर सख्ती की जरूरत बताते हुए सुझाव दिया कि जिन वाहनों का वैध बीमा नहीं है,उन्हें पेट्रोल-डीजल न दिया जाए। साथ ही ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके मालिकों का ई-चालान भी किया जाए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि देश की सड़कों पर चल रहे करीब 56 प्रतिशत वाहन,जिनमें अधिकांश दोपहिया हैं,बिना बीमा के हैं। यह स्थिति मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के उद्देश्य को ही विफल कर देती है। इससे सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। देश में 30.4 करोड़ पंजीकृत वाहनों में से करीब 16.5 करोड़ वाहन बिना बीमा के हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं के 22 प्रतिशत मामलों में बिना बीमा वाले वाहन शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करें,जिसके तहत वाहनों को ईंधन तभी मिले,जब उनका इंश्योरेंस वैध हो। यदि बीमा समाप्त हो चुका है तो संबंधित वाहन को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाए। पीठ के अनुसार,इस व्यवस्था से बिना बीमा और बिना पंजीकरण वाले वाहनों की पहचान आसान होगी तथा वाहन मालिक समय पर बीमा कराने के लिए प्रेरित होंगे।

ई20 विवाद : नितिन गडकरी को हाईकोर्ट से राहत,सोशल मीडिया कंपनियों पर कर सकेंगे केस

मुंबई,05 अगस्त 2026। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ई20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी वीडियो और पोस्ट के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की इजाजत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें मेटा, एक्स और गूगल समेत अज्ञात सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दी है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एआई की मदद से बनाए गए डीपफेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट वायरल हो रहे थे। इनमें गलत तरीके से दिखाया जा रहा था कि नितिन गडकरी और उनके परिवार को सरकार की ई20 इथेनॉल पेट्रोल नीति से आर्थिक फायदा हो रहा है। नितिन गडकरी ने कोर्ट में दलील दी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम उनके मंत्रालय से नहीं जुड़ा है। यह काम पूरी तरह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय देखता है। उनके नाम और परिवार को इस नीति से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट से दो चीजें मांगी हैं। पहली,आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश। दूसरी,उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए 11 करोड़ रुपए का हर्जाना। नितिन गडकरी के वकीलों ने अदालत में कहा कि यह कार्रवाई आम लोगों की राय या चर्चा को दबाने के लिए नहीं है।

प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई व अन्य मुद्दों पर विपक्ष का संसद परिसर में प्रदर्शन

सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र नहीं लाएगी : रिजिजू

नई दिल्ली,05 अगस्त 2026। सरकार परिसीमन पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र नहीं ला रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को इन खबरों को खारिज कर दिया। रिजिजू ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, 'महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन बिल पर 16 से 18 अगस्त के बीच कोई स्पेशल सेशन बुलाने का प्रस्ताव नहीं है।' सरकार मौजूदा मानसून सत्र में ही संविधान संशोधन बिल पास कराने की नई कोशिश कर रही है। इसके लिए रिजिजू ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, राहुल ने समर्थन से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि किरेन रिजिजू ने परिसीमन के मुद्दे पर उनसे बात की। हम इस पर विचार करके उन्हें जवाब देंगे। कांग्रेस और विपक्ष का रुख पहले जैसा ही है। संसद परिसर में कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर चढ़ावा चोरी तथा अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा और गृहमंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग की।

इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर स्थित गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक विरोध मार्च भी निकाला। प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल तथा अन्य विपक्षी दलों के सांसद बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग किया गया और इस पूरे मामले की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। विपक्षी सांसदों ने मांग की कि गृहमंत्री संसद में आकर इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखें। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि छात्रों पर गोली, पैलेट गन, आंसू गैस या लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी की अवश्य होगी। ऐसे आदेश किसी अधिकारी या सरकार के स्तर से ही दिए जाते हैं, इसलिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। देश की लोकतांत्रिक परंपरा यही रही है कि ऐसी घटनाओं के लिए जवाबदेही स्वीकार की जाए।

लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल पास, 135 साल पुराने कानून बदलेंगे

लोकसभा ने बुधवार को बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 को मंजूरी दे दी। यह नया कानून 1891 के ब्रिटिश शासन के समय बने पुराने कानून की जगह लेगा। इस बिल का मकसद यह है कि बैंकों के डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, वर्चुअल और क्लाउड में रखे गए रिकॉर्ड भी अदालत में वैध सबूत (एविडेंस) माने जाएं। लोकसभा में शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया। हंगामा नहीं थमने पर बिना चर्चा के ध्वनिमत (वॉइस वोट) से बिल पास कर दिया गया।

सोनम वांगचुक की अपील पर देवेंद्र महतो ने खत्म की भूख हड़ताल,लाइव बातचीत में मिला रांची आने का भरोसा

रांची,05 अगस्त 2026। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर चल रहा युवाओं का संग्राम अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो की जिद के बीच आखिरकार देश के जाने-माने शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दखल देना पड़ा। वांगचुक के एक खास फोन कॉल ने रांची के इस पूरे आंदोलन की दिशा तय कर दी है, जिसके बाद अनशनकारी देवेंद्र ने एक अहम फैसला लिया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यह पूरा धरना-प्रदर्शन जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत राज्य स्तरीय अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित बड़े पैमाने की धांधली और अनियमितताओं के विरोध में चल रहा है।

सोनम वांगचुक ने फोन पर दी गांधी जी की मिसाल

जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो पिछले कई दिनों से अन्न-जल त्यागकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी अटल जिद थी कि जब तक सोनम वांगचुक खुद रांची आकर उनसे मुलाकात नहीं करते, तब तक वह अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। आंदोलनकारी की बिगड़ती सेहत और गंभीरता को देखते हुए सोनम वांगचुक ने खुद देवेंद्र महतो से फोन पर सीधा संपर्क साधा। बातचीत के दौरान वांगचुक ने उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए समझाया कि अनशन का असली मकसद खुद को शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि गहरी नींद में सोई हुई सत्ता और अंधी सरकार को जगाना होता है। उन्होंने महतो से अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील करते हुए तुरंत शहद और नींबू पानी लेने का आग्रह किया।

रांची आने का मिला पक्का आश्वासन,तब जाकर पिया पानी

फोन पर हुई इस लंबी बातचीत के दौरान देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने अपनी यह दिली ख्वाहिश भी जाहिर की कि वह वांगचुक की मौजूदगी में ही अपना जल ग्रहण करना चाहते हैं। देवेंद्र के इस अटूट विश्वास को देखते हुए वांगचुक ने उन्हें पक्का आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस छात्र आंदोलन का खुला समर्थन करने के लिए खुद रांची पहुंचेंगे। वांगचुक ने बड़े ही प्यार से समझाया कि अगर शरीर में पानी और नमक की कमी हो गई, तो इस लंबी लड़ाई में टिक पाना असंभव हो जाएगा। उनके लगातार समझाने और रांची आने के वादे के बाद आखिरकार देवेंद्र महतो का दिल पसीज गया और उन्होंने पानी ग्रहण कर लिया।

जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

लड़की ने कहा-भारत माता की जय बोलने पर देशद्रोही कहा,शांति से चलने पर भी मारा

नई दिल्ली,05 अगस्त 2026। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में 10 जनपथ पर जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि 20 जुलाई को हुए कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट पर लाठी-पैलेट गन से हमला किया गया। राहुल अपने साथ चार प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं को मीडिया के सामने लाए। एक छात्रा ने कहा- भारत माता की जय बोलने पर हमें देशद्रोही कहा गया।

हम शांति से चल रहे थे तो एक पुलिस अफसर ने शरीर के ऊपरी हिस्से पर मारा। राहुल गांधी ने कहा- प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया। इनका लगातार शोषण हो रहा है। ये बच्चे देश के भविष्य के लिए लड़े। इन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। लोकतंत्र के लिए ये बच्चे लड़े, इसके लिए इनका धन्यवाद।

राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बातें कही- देशभर के युवाओं पर गर्व

- हमने प्रदर्शन कर रहे कुछ युवाओं से बात की। उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट की गई, धमकाया गया और दबाव बनाया गया। मुझे उन पर और देशभर के हजारों युवाओं पर गर्व है। उन्होंने संविधान, भारत के विचार और देश के भविष्य की रक्षा की है।
- राहुल गांधी ने कहा कि पहले छात्रों के घर गुंडे भेजना, 15 साल की एक लड़की से जबरन माफी मंगवाना और फिर उस माफी को स्वीकार करना पूरी तरह बेतुका है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जो सही तरीके से काम करे, परीक्षा पेपर लीक रुकें और देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे।

प्रधानमंत्री के वीडियो पर मेटा ने मांगी माफी

सरकार ने खुद से कंटेंट परोसने को लेकर दी हिदायत

नई दिल्ली,05 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वीडियो हटाए जाने और बाल यौन शोषण एवं दुरुपयोग सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े कथित विज्ञापनों के मामले में मेटा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सरकार से माफी मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने सीएसएएम, डीपफेक सामग्री और मंच के संचालन में हुई त्रुटियों पर खेद व्यक्त किया है। सूत्रों ने बताया कि मेटा ने स्वीकार किया कि कुछ खास तरह की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए काफी पैसा दिया गया था। वहीं,सरकार ने कंपनी को स्पष्ट किया है कि अगर मेटा तय करेगा कि कौन-सा कंटेंट किसे दिखाया जाएगा, तो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत केवल 'मध्यस्थ' (इंटरमीडियरी) के तौर पर मिलने वाला संरक्षण समाप्त हो जाएगा। मेटा के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी जोएल कैपलन के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की।

तमिलनाडु बजट में सोने की सौगात...नवजात को अंगूठी और शादी में बड़ा उपहार देगी सरकार

तमिलनाडु,05 अगस्त 2026। तमिलनाडु की सी. जोसेफ विजय की टीवीके सरकार ने बुधवार, 5 अगस्त 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने बजटीय भाषण के दौरान आम जनता, महिलाओं और छात्र-छात्राओं के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इस बजट का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय राहत देना और राज्य के सामाजिक कल्याण ढांचे को मजबूती प्रदान करना है। बजट भाषण में वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए दो विशेष योजनाओं की घोषणा की। 'अन्नन सीर योजना' के तहत प्रदेश में युवतियों के विवाह के अवसर पर सरकार की ओर से 8 ग्राम (एक सवेरेन) सोने का सिक्का और एक रेशमी साड़ी उपहार स्वरूप दी जाएगी। इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बजट में 812 करोड़ रुपये की राशि

निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर, सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए 'थाई मामन थंगा मोथिरा थिट्टम' योजना शुरू की गई है,जिसके तहत वहां जन्म लेने वाले हर नवजात शिशु को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस पहल के लिए 560 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तमिलनाडु में हुए हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ताधारी तमिलगा वेत्री कड़गम ने जनता से सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कई वादे किए थे। नई सरकार का यह पहला बजट उन्हीं वादों को धरातल पर उतारने की एक कोशिश माना जा रहा है। शादी-ब्याह के समय होने वाले वित्तीय दबाव को कम करने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं को पुनर्गठित कर नए रूप में पेश किया गया है। विधानसभा में बजट दस्तावेज रखते हुए वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा यह बजट तमिलनाडु के हर नागरिक के कल्याण और राज्य की आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

हमारी सरकार का लक्ष्य केवल वित्तीय आवंटन करना नहीं,बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। बजट में स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए भी बड़ा फंड तय किया गया है।

कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बनेगी राजनीतिक पार्टी,प्रेशर ग्रुप के तौर पर जारी रहेगा आंदोलन : अभिजीत दिपके

नई दिल्ली,05 अगस्त 2026। दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने अगले चरण की रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संगठन की दो दिवसीय कोर टीम की बैठक बुधवार से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में संस्थापक अभिजीत दिपके के आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन के संस्थापक, राष्ट्रीय प्रवक्ता और कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य हालिया छात्र आंदोलनों की समीक्षा करना और आने वाले समय में संगठन की दिशा तय करना बताया गया है।

प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करने पर रहेगा फोकस : बैठक शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए अभिजीत दिपके ने संगठन की प्राथमिकताओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल सीजेपी किसी राजनीतिक दल के रूप में काम करने की योजना नहीं बना रही है। उनका कहना था कि संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार पर युवाओं, छात्रों, शिक्षा और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रभावी दबाव बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी छात्रों को संगठन की आवश्यकता होगी, वहां सीजेपी उनके समर्थन में खड़ी दिखाई देगी।

आगे की रणनीति पर होगा विस्तृत विचार-विमर्श : अभिजीत दिपके ने बताया कि दो दिवसीय बैठक में संगठन के भविष्य के रोडमैप पर गहन चर्चा की जाएगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि आने वाले समय में सीजेपी किस प्रकार अपने अभियानों को आगे बढ़ाएगी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ध्यान शिक्षा, रोजगार और छात्रों की समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। बैठक के समापन के बाद गुरुवार दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की जाएगी।

कई राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा

दिपके के अनुसार बैठक में केवल छात्र आंदोलन ही नहीं, बल्कि कई अन्य समकालीन विषयों पर भी विचार किया जाएगा। इनमें एथेनॉल मिश्रित ईंधन, बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, मीडिया की भूमिका तथा न्यायपालिका जैसी संस्थाओं में जनता के घटते भरोसे जैसे मुद्दे शामिल हैं। संगठन इन विषयों पर अपनी आगे की नीति और अभियान की दिशा तय करेगा, ताकि व्यापक स्तर पर जनसमर्थन जुटाया जा सके।

झारखंड के आंदोलनरत छात्रों को दिया समर्थन

सीजेपी ने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन का भी ऐलान किया है। अभिजीत दिपके ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता पहले से ही वहां के छात्र नेताओं के संपर्क में हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो सीजेपी के सदस्य आंदोलन में भी भाग लेंगे। उन्होंने दोहराया कि संगठन का उद्देश्य छात्रों की आवाज को मजबूत करना है।

एक लाख का इनामी बदमाश फुरकान मुठभेड़ में ढेर,पुलिसकर्मी के पेट में लगी गोली

नई दिल्ली,05 अगस्त 2026। यूपी में बुधवार की दोपहर दिनदहाड़े एनकाउंटर में पुलिस ने एक लाख के इनामी फुरकान को मार गिराया है। शामली में झिंझाना थानाक्षेत्र में रंगाना फार्म के पास एनकाउंटर हुआ है। फुरकान का नाम कैराना पलायन में चर्चा में आया था। 2014 में फुरकान ने एक व्यापारी की रंगदारी नहीं देने पर दिनदहाड़े हत्या कर दी थी। उसी के बाद पलायन का मामला उठा था। फुरकान पर लूट और हत्या के प्रयास के मामलों में वांछित था। उसके खिलाफ लूट, हत्या, डकैती के लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं। कुख्यात फुरकान का आतंक कैराना के अलावा अन्य जनपदों में भी व्याप्त है। बताया जा रहा कि वह चार पांच माह पहले ही जेल से जमानत पर आया था। इसके बाद कैराना और कांधला में लूट और हत्या का प्रयास में वांछित चल रहा था। बुधवार की दोपहर पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान बदमाशों के रंगाना में होने की सूचना मिली।

जैसे ही पुलिस पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश को लगी उसकी मौत हो गयी। मारे गए बदमाश की शिनाख्त एक लाख के इनामी फुरकान के रूप में हुई है। पुलिस ने हिस्ट्री निकाली तो उस पर लूट,हत्या,डकैती,रंगदारी आदि के लगभग 30 मुकदमे दर्ज मिले। फुरकान का कैराना में आतंक रहा है। उस समय मुकीम काला और फुरकान दोनों गैंग का आंतक था। मुकीम गैंग को पुलिस लगभग खत्म कर चुकी है जबकि फुरकान अभी भी अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। फुरकान के डर से कैराना के व्यापारी पलायन को मजबूर हो गए थे।

संपादकीय

हर तीन साल में डेस्क बदलेगी, लेकिन क्या व्यवस्था भी बदलेगी?

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के नए परिपत्र के अनुसार अब शासकीय कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों के कार्य-पटल (Desk Assignment) का प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से परिवर्तन किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी,पारदर्शिता आएगी,जवाबदेही मजबूत होगी और कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों का अनुभव मिलेगा। सिद्धांत रूप से यह निर्णय स्वागत योग्य है। किसी भी कार्यालय में वर्षों तक एक ही व्यक्ति का एक ही डेस्क पर बने रहना कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। एक ही शाखा में लंबे समय तक जमे रहने से न केवल एकाधिकार की स्थिति बनती है,बल्कि कई बार अनौपचारिक प्रभाव,व्यक्तिगत नेटवर्क और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए समय-समय पर कार्य-पटल बदलना सुशासन का एक आवश्यक हिस्सा माना जाता है।

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या केवल आदेश जारी करने से व्यवस्था बदल जाएगी?

सरकारी कार्यालयों में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे,जहां एक ही कर्मचारी वर्षों नहीं,बल्कि दशकों तक एक ही शाखा में बैठा रहता है। फाइलें उसी की मेज से गुजरती हैं,नियमों की व्याख्या वही करता है और आम नागरिक के लिए वही कार्यालय का सबसे प्रभावशाली चेहरा बन जाता है। कई बार अधिकारी बदल जाते हैं,लेकिन शाखा संभालने वाला कर्मचारी नहीं बदलता। परिणामस्वरूप कार्यालय का वास्तविक नियंत्रण भी उसी के हाथों में चला जाता है।

सरकार ने अपने आदेश में यह भी प्रावधान रखा है कि विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमोदन से किसी कर्मचारी को उसी डेस्क पर बनाए रखा जा सकता है। यहीं सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है। यदि विशेष परिस्थिति ही सामान्य नियम बन गई,तो यह पूरा आदेश कागजों तक सीमित होकर रह जाएगा। इसलिए इस अपवाद का उपयोग अत्यंत सीमित और पारदर्शी होना चाहिए।

यह भी ध्यान रखना होगा कि केवल डेस्क बदलने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता। यदि कार्य संस्कृति नहीं बदली,जवाबदेही तय नहीं हुई और प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन नहीं हुआ,तो कर्मचारी केवल एक मेज से दूसरी मेज तक स्थानांतरित होंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी।

सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि डेस्क परिवर्तन केवल कनिष्ठ कर्मचारियों तक सीमित न रहे। यदि पारदर्शिता उद्देश्य है,तो संवेदनशील शाखाओं में पदस्थ सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर समान रूप से यह नीति लागू होनी चाहिए। चयनात्मक अनुपालन से इस आदेश की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठेंगे। आज आम नागरिक सरकारी कार्यालय में किसी कर्मचारी का नाम नहीं,बल्कि उसकी सीट पहचानता है। लोग कहते हैं...उस सीट वाले बाबू से मिलिए,वही काम कराएंगे। यह स्थिति स्वयं बताती है कि कई कार्यालयों में व्यक्ति नहीं,बल्कि सीटें स्थायी शक्ति केंद्र बन चुकी हैं। यदि नया आदेश इस संस्कृति को बदलने में सफल होता है,तो यह प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम होगा।
लेकिन सरकार की परीक्षा आदेश जारी करने में नहीं,बल्कि उसके पालन में है। क्या तीन वर्ष पूरे होने पर वास्तव में हर कार्यालय में डेस्क बदलेगी? क्या अनुपालन की निगरानी होगी? क्या उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा।
सुशासन की पहचान अच्छे परिपत्रों से नहीं,बल्कि उनके ईमानदार क्रियान्वयन से होती है। यदि यह आदेश फाइलों से निकलकर कार्यालयों की वास्तविक कार्यसंस्कृति बदल सका,तभी इसे प्रशासनिक सुधार कहा जाएगा,अन्यथा यह भी सरकारी आदेशों की लंबी सूची में एक और दस्तावेज़ बनकर रह जाएगा।

उपचुनावों का जनादेश : क्या बदल रहा है मतदाता का मिजाज?

छोटे चुनावों में छिपे बड़े राजनीतिक संदेश

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

लोकतांत्रिक राजनीति में कई बार छोटे चुनाव भी बड़े संदेश दे जाते हैं। विधानसभा उपचुनावों को लंबे समय तक केवल रिक्त सीटों को भरने की औपचारिक प्रक्रिया माना जाता रहा है। सामान्य धारणा यही रही कि जिस राज्य में जिस दल की सरकार होती है, प्रशासनिक बढ़त,संगठनात्मक शक्ति और सत्ता के प्रभाव के कारण वही दल उपचुनाव आसानी से जीत जाता है। इसी कारण उपचुनावों के परिणामों को व्यापक राजनीतिक संकेतक के रूप में कम ही देखा जाता था किंतु पिछले कुछ वर्षों में यह धारणा तेजी से बदली है। अब उपचुनाव केवल एक सीट का फैसला नहीं करते बल्कि जनता के तत्कालीन मनोभाव,सरकार के प्रति संतोष-असंतोष,संगठन की मजबूती, नेतृत्व की स्वीकार्यता और भविष्य की राजनीतिक दिशा के संकेत भी देते हैं। बिहार के बांकीपुर,मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनावों ने भी यही संदेश दिया है। तीन सीटों में से दो पर भाजपा की हार और केवल एक पर जीत ने राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या ये केवल स्थानीय परिस्थितियों का परिणाम हैं अथवा भाजपा के सामने उभर रही नई राजनीतिक चुनौतियों का प्रारंभिक संकेत? उपचुनाव सत्ता परिवर्तन का जनादेश नहीं होते किंतु वे जनता के बदलते मानस की पहली आहट अवश्य होते हैं और यही कारण है कि इन परिणामों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।

सबसे अधिक चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की रही। यह सीट केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं थी बल्कि भाजपा की राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। लगभग तीन दशक से यह भाजपा का अभेद्य दुर्ग रहा। पहले भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन के पिता और बाद में स्वयं नितिन नवीन लगातार यहां विजय प्राप्त करते रहे। नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट रिक्त हुई और भाजपा को अटूट विश्वास था कि उसका यह गढ़ सुरक्षित रहेगा किंतु जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने न केवल भाजपा का यह किला ध्वस्त कर दिया बल्कि बिहार की राजनीति में नए विकल्प की संभावनाओं को भी मजबूत कर दिया। यह परिणाम केवल भाजपा की हार नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक चूक का भी परिणाम माना जा रहा है। उम्मीदवार चयन में अंतिम समय तक बना भ्रम, स्थानीय कार्यकर्ताओं की असंतुष्टि और अत्यधिक आत्मविश्वास ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। लंबे समय तक किसी सीट पर लगातार जीत कभी-कभी संगठन में आत्मसंतोष पैदा कर देती है। यही स्थिति बांकीपुर में दिखाई दी। भाजपा ने शायद मान लिया था कि उसका पारंपरिक वोट बैंक और संगठनात्मक नेटवर्क किसी भी परिस्थिति में जीत सुनिश्चित कर देगा जबकि मतदाता पहले की तुलना में अधिक सजग और स्वतंत्र निर्णय लेने वाला बन चुका है। बांकीपुर का परिणाम प्रशांत किशोर के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में अनेक दलों को सफलता दिलाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार स्वयं चुनावी परीक्षा में उतरे और सफल हुए। हालांकि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तरह विफल रही थी किंतु इस विजय ने सिद्ध कर दिया कि यदि कोई दल लगातार जनता के बीच बना रहे और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाए तो वह स्थापित राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दे सकता है। यह जीत बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को भी बल देती है।
दूसरी ओर मध्य प्रदेश की दतिया सीट भाजपा के लिए और अधिक चिंता का विषय है। भाजपा की यह हार केवल विपक्ष की सफलता नहीं बल्कि भाजपा संगठन के भीतर असंतोष की अभिव्यक्ति भी मानी जा रही है। पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद उनके समर्थकों की नाराजगी चुनाव अभियान के दौरान लगातार चर्चा में रही। चुनावी राजनीति में उम्मीदवार केवल पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता बल्कि स्थानीय संगठन की भावनाओं का केंद्र भी होता है। जब कार्यकर्ता स्वयं उत्साहहीन हो जाएं या भीतरघात की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो मजबूत संगठन भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता। दतिया का परिणाम इसी सत्य की पुष्टि करता है। मध्य प्रदेश भाजपा लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अत्यंत मजबूत संगठनात्मक ढांचे के लिए जानी जाती रही। संगठन, सरकार और जनता के बीच संवाद की जो परंपरा विकसित हुई थी,नेतृत्व परिवर्तन के बाद उसे उसी प्रभावशीलता से बनाए रखना नई सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। उपचुनावों ने संकेत दिया है कि केवल सत्ता में होना पर्याप्त नहीं, संगठन की एकजुटता और स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता भी उतनी ही आवश्यक है।
गुजरात के मांझलपुर में भाजपा ने जीत दर्ज कर अपनी संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन अवश्य किया किंतु मतों के अंतर में आया परिवर्तन संकेत देता है कि वहां भी विपक्ष धीरे-धीरे अपनी जमीन मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि गुजरात में भाजपा की स्थिति अभी भी सुदृढ़ है,फिर भी चुनावी आंकड़े बताते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए आत्मसंतोष उचित नहीं हो सकता। इन उपचुनावों की चर्चा का एक महत्वपूर्ण पक्ष 'जेन-जी आंदोलन' भी रहा। चुनाव 30 जुलाई को ऐसे समय हुए,जब प्रतियोगी परीक्षा,पेपर लीक,रोजगार, अवसरों की कमी, प्रशासनिक जवाबदेही इत्यादि युवाओं से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में थे। निश्चित रूप से यह कहना कठिन होगा कि केवल इसी आंदोलन ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया क्योंकि प्रत्येक उपचुनाव में स्थानीय समीकरण,उम्मीदवार की लोकप्रियता और संगठनात्मक स्थिति कहीं अधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि युवाओं के बीच बढ़ती असंतुष्टि का व्यापक राजनीतिक वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। यदि युवा मतदाता किसी सरकार के प्रति निराशा महसूस करता है तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव चुनावी व्यवहार पर भी दिखाई दे सकता है। आज का मतदाता (विशेषकर युवा वर्ग) केवल जातीय या पारंपरिक राजनीतिक पहचान के आधार पर मतदान नहीं कर रहा,रोजगार,शिक्षा,भ्रष्टाचार,पारदर्शिता, सुशासन,अवसरों की समानता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व जैसे मुद्दे उसकी प्राथमिकता बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल संचार ने भी मतदाता को पहले से अधिक जागरूक बनाया है। अब सरकारों के लिए केवल विकास के दावे पर्याप्त नहीं,उनके ठोस परिणाम भी दिखाई देने चाहिएं।

भाजपा के लिए इन परिणामों से सबसे बड़ा सबक उम्मीदवार चयन को लेकर है। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में देखा गया है कि टिकट वितरण को लेकर स्थानीय स्तर पर असंतोष उत्पन्न हुआ है। संगठन की राय,कार्यकर्ताओं की भावनाओं और स्थानीय लोकप्रियता की उपेक्षा कभी-कभी चुनावी नुकसान का कारण बन जाती है। यदि पार्टी समय रहते इस पहलू पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो भविष्य के बड़े चुनावों में भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। भाजपा को यह भी समझना होगा कि कोई भी राजनीतिक गढ़ स्थायी नहीं होता। लोकतंत्र में जनता समय-समय पर अपने निर्णय बदलती है और वही दल लंबे समय तक सफल रहता है,जो निरंतर आत्म-मूल्यांकन करता रहे। उपचुनावों ने भाजपा को यही संदेश दिया है कि संगठन की मजबूती,नेतृत्व की विश्वसनीयता और जनता के साथ सतत संवाद बनाए रखना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। हालांकि इन परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल रहा है। तीन विधानसभा सीटों के परिणाम किसी सरकार की लोकप्रियता का अंतिम पैमाना नहीं हो सकते,फिर भी लोकतंत्र में छोटे संकेतों की उपेक्षा करना भी राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता क्योंकि यही छोटे संकेत आगे चलकर बड़े राजनीतिक परिवर्तनों की भूमिका तैयार करते हैं।

विपक्ष के लिए ये परिणाम आशा का संदेश हैं किंतु यह आशा तभी सार्थक होगी,जब वह केवल सत्ता विरोधी वातावरण पर निर्भर रहने के बजाय विश्वसनीय नेतृत्व,स्पष्ट वैकल्पिक नीति और मजबूत संगठन प्रस्तुत कर सके। वहीं जन सुराज जैसे नए राजनीतिक दलों के लिए यह अवसर भी है और परीक्षा भी। एक सीट की सफलता को व्यापक जनविश्वास में बदलना कहीं अधिक कठिन कार्य होगा। इन उपचुनावों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि मतदाता पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक,अधिक अपेक्षाकारी और अधिक स्वतंत्र निर्णय लेने वाला हो चुका है। अब चुनाव केवल संगठनात्मक शक्ति या पुराने राजनीतिक समीकरणों से नहीं जीते जा सकते। जनता नेतृत्व की विश्वसनीयता, उम्मीदवार की स्वीकार्यता, स्थानीय मुद्दों के समाधान और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि को भी उतना ही महत्व देती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति अंततः जनता ही होती है और जनता समय-समय पर छोटे चुनावों के माध्यम से भी बड़े संदेश देना कभी नहीं भूलती।

नौजवानों को निगलता नशे का अदृश्य संकट

संजीव कुमार ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे,मन का बल बढ़ाए और मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा कर दे,नशा शिक्षा,चरित्र और आत्मबल तीनों का सबसे बड़ा शत्रु है। मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी संवेदना और बचपन की मासूमियत है। संवेदना मनुष्य को मनुष्य बनाती है और बचपन उसके व्यक्तित्व की नींव रखता है। किंतु आज नशीले पदार्थों का बढ़ता जाल इन दोनों पर सबसे कड़ा प्रहार कर रहा है। नशा केवल शरीर को नहीं,बल्कि विवेक,करुणा,परिवार,शिक्षा, संस्कृति और भविष्य को भी नष्ट कर देता है। जिस आयु में बच्चों के हाथों में पुस्तकें और सपने होने चाहिए,वहाँ यदि नशे का जहर पहुँच जाए तो आने वाला पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ड्रग्स,सिंथेटिक नशे,हेरोइन, चरस,गांजा,अफीम तथा नशीली गोलियों का प्रसार चिंताजनक रूप से बढ़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार देश में करोड़ों लोग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। 2019 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 16 करोड़ लोग शराब, 3 करोड़ से अधिक लोग भांग या गांजा तथा लगभग 2.3 करोड़ लोग ओपिओइड (अफीम, हेरोइन आदि) का सेवन करते पाए गए। इनमें बड़ी संख्या 10 से 17 वर्ष और 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की है। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में पंजाब,मणिपुर, मिजोरम,नागालैंड,अरुणाचल प्रदेश,राजस्थान, उत्तर प्रदेश,दिल्ली,हरियाणा,महाराष्ट्र तथा गोवा प्रमुख हैं। पंजाब में हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स का गंभीर संकट लंबे समय से चिंता का विषय है। पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा पार से होने वाली तस्करी ने युवाओं को प्रभावित किया है। राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मादक पदार्थों की तस्करी लगातार बढ़ी है। महानगरों में नशीली गोलियां, कोकीन और पार्टी ड्रग्स तेजी से फैल रहे हैं। सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि नशे की शुरुआत अब किशोरावस्था में ही होने लगी है। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों,पारिवारिक विघटन,बेरोजगारी, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, गलत संगति तथा मानसिक तनाव के कारण अनेक बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। परिणामस्वरूप पढ़ाई छूट जाती है,अपराध बढ़ते हैं,हिंसा और आत्महत्या की प्रवृत्ति विकसित होती है तथा परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। नशा सबसे पहले मनुष्य की संवेदना को समाप्त करता है। जो व्यक्ति कभी माता-पिता के प्रति श्रद्धावान था,वही नशे की लत में उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। परिवार की जमा पूंजी नशे में समाप्त हो जाती है। अनेक युवा चोरी, लूट और अन्य अपराधों की ओर बढ़ जाते हैं। धीरे-धीरे रिश्तों की गर्माहट समाप्त होने लगती है और मनुष्य केवल नशे का दास बनकर रह जाता है।
महात्मा गांधी ने कहा था शराब और नशा मनुष्य की आत्मा का पतन कर देते हैं। डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का संदेश था शिक्षित बनो,संगठित रहो और संघर्ष करो। यह संदेश नशामुक्त समाज की स्थापना के लिए भी उतना ही आवश्यक है। नशे के विरुद्ध केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं। परिवार, विद्यालय,समाज,धार्मिक संस्थाएँ,मीडिया तथा शासन सभी को मिलकर कार्य करना होगा। बच्चों

के साथ संवाद बढ़ाना,खेल,साहित्य,संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना,विद्यालयों में नशामुक्ति शिक्षा को अनिवार्य बनाना तथा नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास की प्रभावी व्यवस्था करना समय की आवश्यकता है। सीमाओं पर तस्करी रोकने के साथ-साथ ऑनलाइन अवैध नेटवर्क पर भी कठोर कार्रवाई आवश्यक है।
यदि किसी राष्ट्र का बचपन सुरक्षित है तो उसका भविष्य भी सुरक्षित है। लेकिन यदि बचपन नशे की गिरफ्त में चला गया,तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल आर्थिक ही नहीं, नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी कमजोर हो जाएँगी। इसलिए नशे के विरुद्ध संघर्ष केवल स्वास्थ्य का नहीं,बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान है।

आइए संकल्प लें कि हम अपने घर,विद्यालय, समाज और कार्यस्थल पर नशामुक्ति का संदेश फैलाएँगे। हर बच्चे के हाथ में नशा नहीं,पुस्तक होगी;हर युवा की आँखों में धुंध नहीं,सपने होंगे; और हर परिवार में भय नहीं,संवेदना और विश्वास का वातावरण होगा। यही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत की वास्तविक पहचान बनेगी।

वर्ष 2025-26 तक उपलब्ध सरकारी आँकड़े बताते हैं कि भारत में नशीले पदार्थों की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और बाल संरक्षण का गंभीर संकट बन चुकी है। गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार नशे की तस्करी पर लगातार कार्रवाई के बावजूद इसकी पहुँच बच्चों और युवाओं तक बढ़ रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा एम्स के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 10-17 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 20 लाख बच्चे कैनाबिस (गांजा),40 लाख बच्चे ओपिओइड (अफीम, हेरोइन आदि),30 लाख बच्चे इनहेलेंट (सूँघने वाले नशीले पदार्थ) तथा लगभग 20 लाख बच्चे नशीली दवाओं (सेडेटिव) के सेवन से प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विद्यालय छोड़ने वाले किशोरों और शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों में यह समस्या अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दे रही है।

मार्च 2025 में संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 2023-24 में देशभर के ओपन शेल्टरों में रहने वाले 4,158 बच्चों की पहचान नशे से प्रभावित बच्चों के रूप में की गई। यह आँकड़े केवल सरकारी आश्रय गृहों में चिन्हित बच्चों के हैं; वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2020 से मई 2025 तक राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने 116 बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी मामलों का भंडाफोड़ करते हुए लगभग 1,09,318 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए। यह दर्शाता है कि भारत न केवल नशे की खपत बल्कि अंतरराष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क की चुनौती से भी जूझ रहा है।

विकास की नींव या भ्रष्टाचार की बुनियाद?

अजय कुमार,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटा था और उस वक्त इस 63 किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर की तुलना जर्मनी की सड़कों से की गई थी। 4,200 करोड़ रुपये की इस परियोजना का सपना बड़ा था,लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक निकली। उद्घाटन के महज तेरह दिन बाद उन्नाव जिले के कोरारी के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा कई मीटर तक धंस गया। एनएचएआई ने इसे स्लिपेज की समस्या और नियमित रखरखाव का हिस्सा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, मगर चार दिन बाद ही यही सड़क दोबारा धंस गई। जुलाई खत्म होते-होते यह सिलसिला कम से कम पांच बार दोहराया जा चुका था। जिस सड़क को देश के सबसे महंगे टोल वाले एक्सप्रेसवे के रूप में पेश किया गया,वह हल्की बारिश भी नहीं झेल पाई। सवाल यह नहीं कि बारिश कितनी हुई,सवाल यह है कि जो सड़क सामान्य मानसून के पहले ही झटके में उखड़ जाए,उसकी नींव में आखिर डाला क्या गया था। यह अकेला उदाहरण नहीं है। इसी साल मई के आखिरी हफ्ते में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा तेज तूफान के दौरान ढह गया था,जिसमें कम से कम छह मजदूरों की जान चली गई थी। जुलाई के मध्य में देहरादून-पांवटा साहिब मार्ग पर टौंस नदी पर बना सोलह करोड़ रुपये का पुल,जिस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुए मुश्किल से एक दिन बीता था,पहली बड़ी बारिश में ही जगह-जगह धंस गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह पुल पहले भी एक बार बह चुकी अस्थायी पुलिया की जगह जल्दबाजी में बनाया गया था। जून के आखिर में असम में एक पुल पूरी तरह बह गया,और गांव वालों ने बताया कि उन्होंने निर्माण के समय लोहे के बजाय पक्के कंक्रीट के पुल की मांग की थी, जिसे अनसुना कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि नदी पार स्कूल जाने वाले बच्चों और खेतों तक पहुंचने वाले किसानों का रास्ता ही बंद हो गया।

यह पैटर्न किसी एक राज्य या किसी एक ठेकेदार तक सीमित नहीं है,यह पूरे देश के निर्माण तंत्र की बीमारी बन चुका है। संसद में हाल ही में केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया कि इस समय देश भर में 1,191 नेशनल हाईवे परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 629 यानी करीब आधी परियोजनाएं तय समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकीं। इतना ही नहीं,वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच घटिया गुणवत्ता के काम को लेकर 103 ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। यह आंकड़ा खुद बताता है कि निर्माण में गड़बड़ी कोई इक्का-दुक्का घटना नहीं,बल्कि व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। इसी दौर में हुए दुर्घटना विश्लेषण के आधार पर देश भर में 6,358 ऐसे सड़क हिस्सों को ब्लैक कॉरिडोर के रूप में चिह्नित किया गया है,जहां बार-बार हादसे होते हैं। यानी जिन सड़कों को सुरक्षित और टिकाऊ बताकर जनता के पैसे से बनाया गया, उनमें से हजारों हिस्से खुद खतरे की निशानी बन चुके हैं। सवाल यह भी उठता है कि जब गुणवत्ता की जांच और ठेकेदारों पर कार्रवाई का तंत्र मौजूद है,तो फिर हर मानसून में यही कहानी क्यों दोहराई जाती है। जवाब निर्माण से जुड़े हर व्यक्ति को पता है, मगर खुलकर कोई नहीं बोलता। जहां भी सरकारी निर्माण होता है,वहां कमीशनखोरी एक अघोषित लेकिन तयशुदा नियम बन चुकी है। ठेका मिलने से पहले ही तय हो जाता है कि किस स्तर पर कितना प्रतिशत व्यवस्था में जाएगा,और जब असली निर्माण सामग्री और मजदूरी में से इतना हिस्सा पहले ही निकाल लिया जाता है, तो बाकी बचे बजट में मजबूत सड़क या पुल बनना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे जैसी परियोजना, जिसे देश के सबसे आधुनिक कॉरिडोर के रूप में प्रचारित किया गया,दो हफ्ते में मरम्मत का मोहताज बन गई। निलंबन और ब्लैकलिस्टिंग जैसी कार्रवाइयां देखने में सख्त लगती हैं,लेकिन असर में बेहद कमजोर साबित होती हैं। जांच पूरी होने तक तीन इंजीनियरों को काम से हटाना एक रस्म भर है,क्योंकि आगे चलकर वही अधिकारी किसी और परियोजना में लौट आते हैं। घटिया निर्माण के दोषी ठेकेदार भी काली सूची में डाले जाने के बाद नाम और कंपनी का ढांचा बदलकर नए सिरे से टेंडर भरने लगते हैं। यह खेल इतना पुराना और इतना संगठित हो चुका है कि अब इसे रोकने वाला कोई डर बाकी नहीं बचा। दिलचस्प यह भी है कि अंग्रेजों के जमाने में बने पुल,रेलवे पुल और सड़कें आज भी सौ-सौ साल बाद मजबूती से खड़ी हैं,जबकि आजादी के बाद और खासकर हाल के वर्षों में बनी कई परियोजनाएं उद्घाटन के हफ्तों के भीतर बिखरने लगती हैं।

महँगाई की नई किस्त आ गई,नाम रखा गया : बस किराया

प्रो. आर के जैन अरिजीत
बड़वानी,मध्यप्रदेश

लोकतंत्र में जनता मालिक है... बस भुगतान करने तक

क्या सरकार का हर समझौता आम आदमी की जेब से ही होगा?

मध्य प्रदेश की सड़कों पर आज केवल बस किराया नहीं बढ़ा,बल्कि आम आदमी की जेब पर नया आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। परिवहन विभाग के ताज़ा नोटिफिकेशन ने बस किराया सवा रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर दो रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया है। यह महज़ किराया वृद्धि नहीं,बल्कि ऐसा मौन कर है जिसे न किसी बजट में प्रस्तुत किया गया,न विधानसभा में उस पर गंभीर बहस हुई। बस ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल की चेतावनी के आगे सरकार झुक गई और उसका पूरा भार सीधे यात्रियों पर डाल दिया। डीज़ल महँगा हुआ है,संचालन लागत बढ़ी है—ये तर्क वर्षों से दिए जाते रहे हैं। पर सबसे चिंताजनक यह है कि राज्य की सड़कों पर चलने का अधिकार अब केवल उसी के लिए सहज है,जो बढ़ती महँगाई का बोझ उठा सके।

इस पूरे घटनाक्रम में सरकार और बस संचालक दो विरोधी पक्ष नहीं,बल्कि एक ही व्यवस्था के दो चेहरे हैं। संचालक कहते हैं कि पाँच वर्षों से किराया नहीं बढ़ा,डीज़ल सौ रुपये लीटर के पार पहुँच गया और खर्च बढ़ रहा है। सरकार नोटिफिकेशन जारी कर जिम्मेदारी पूरी मान लेती है। दोनों मिलकर ऐसा समीकरण गढ़ते हैं, जिसमें हर बढ़ी लागत का भुगतान केवल यात्री करता है। इस समीकरण में न संचालकों की कार्यकुशलता पर सवाल उठते हैं, न सरकारी नीतियों की कमियाँ। नतीजा यह है कि सौ किलोमीटर की यात्रा पर यात्री को लगभग पचहत्तर रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। लंबी दूरी तय करने वाले परिवारों के लिए यह अतिरिक्त राशि महीने भर की सब्जियों के खर्च के बराबर बैठती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस निर्णय में आम आदमी न सहभागी है,न हितधारक;वह केवल अंतिम भुगतानकर्ता है।
यही कहानी रसोई तक पहुँचते-पहुँचते और कड़वी हो जाती है। खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। शक्कर लगभग पच्चीस प्रतिशत महँगी हो चुकी

है। तुअर और चना दाल के दाम बढ़े हैं। मैदा और खाद्य तेल भी चुपचाप महँगे हो गए हैं। त्योहारों से पहले रसोई का बजट बिगड़ना महज़ संयोग नहीं। परिवहन महँगा होने का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ता है और अंततः अनाज,दाल, सब्ज़ी तथा रोजमर्रा की हर वस्तु महँगी हो जाती है। एक ओर सरकार राशन कार्ड और सब्सिडी की बात करती है,दूसरी ओर वही नागरिक सड़क पर सफर करते समय और रसोई में भोजन बनाते समय महँगाई का अतिरिक्त कर चुकाने को मजबूर होता है। यह दोहरी मार गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को लगातार सिकोड़ रही है।
इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया है। किराया बोर्ड की बैठक हुई, मंत्री स्तर पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री की सहमति का हवाला दिया गया और नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जनता कहाँ थी? विपक्ष की भूमिका क्या थी? नागरिक समाज की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? लोकतंत्र की विडंबना यही है कि जब प्रत्यक्ष कर बढ़ते हैं तो सदन में तीखी बहस होती है,लेकिन जब बस किराया बढ़ता है तो सब कुछ एक सरकारी गजट की खामोशी में सिमट जाता है। हड़ताल की आशंका ने सरकार को झुका दिया,पर उसी निर्णय ने करोड़ों यात्रियों को पूरी तरह असहाय बना दिया। सत्ता और पूँजी का यह सहज गठजोड़ अब इतना सामान्य हो गया है कि उस पर प्रश्न उठाने वाले भी कम दिखाई देते हैं।

आम आदमी के लिए यह निर्णय केवल कुछ रुपये बढ़ने का मामला नहीं है। यह उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके अवसरों और उसकी गतिशीलता पर सीधा प्रहार है। खेत या फैक्ट्री जाने वाला मजदूर,परीक्षा देने निकलने वाला छात्र,इलाज के लिए अस्पताल जाने वाला मरीज—हर व्यक्ति की यात्रा अब पहले से अधिक महँगी हो गई है। जब यात्रा महँगी होती है तो शिक्षा,स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुँच भी महँगी हो जाती है। सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है,लेकिन उसी विकास की सड़क पर चलने की कीमत आम नागरिक से वसूलती है। यह विकास का विस्तार नहीं,बल्कि विकास के अवसरों का संकुचन है।

यदि यह निर्णय वास्तव में व्यावहारिक होता तो सरकार केवल किराया बढ़ाने का रास्ता नहीं चुनती। वह बस संचालकों को संचालन में दक्षता बढ़ाने,अनावश्यक खर्च कम करने और मार्गों के बेहतर प्रबंधन के लिए बाध्य करती। यदि यह निर्णय न्यायसंगत होता तो बढ़े हुए आर्थिक बोझ का कुछ हिस्सा राज्य स्वयं वहन करता या कम से कम किराया चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाता। लेकिन सरकार ने सबसे आसान विकल्प चुना—हड़ताल टालने के लिए यात्री को ही बलि का बकरा बना दिया। यह प्रशासनिक विवेक नहीं,बल्कि शासन की कमजोरी का परिचायक है। वास्तविक साहस तब दिखाई देता,जब सरकार संचालकों के सामने कठोर शर्तें रखती और जनता को राहत देने का रास्ता निकालती।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

सुपरमैन की उड़ान जारी... छोटे खिलाड़ी आउट,लेकिन 'विलेन' अब भी स्क्रिप्ट से गायब!

इंजेक्शन,कैप्सूल,महुआ शराब के बाद अब 18 पेटियों में 900 पाव मध्यप्रदेश की गोवा व्हिस्की जब्त...सुपरमैन

रंजीत गुप्ता की लगातार कार्रवाई से चर्चा तेज,लेकिन सवाल वही-क्या असली 'डॉन' अब भी पर्दे के पीछे है?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

संभागीय आबकारी उड़नदस्ता के सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता को लोग अब मजाक-मजाक में नहीं,बल्कि गंभीरता से'सुपरमैन'कहने लगे हैं। कारण भी साफ है। पिछले कुछ महीनों में शायद ही कोई ऐसा सप्ताह गुजरा हो,जब उनकी टीम ने किसी न किसी नशे के कारोबारी,कथित सप्लायर या अवैध शराब तस्कर को पकड़कर जेल नहीं भेजा हो। ताजा कार्रवाई में उड़नदस्ता ने उदयपुर क्षेत्र के नुनेरा गांव से मध्यप्रदेश की 18 पेटियों में रखी 900 पाव (162 लीटर) गोवा व्हिस्की जब्त कर दो आरोपियों–ब्रिजलाल पैकरा और गौरव जायसवाल–को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आबकारी विभाग के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पंच ब्रिजलाल पैकरा के घर दबिश दी गई, जहां भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पूछताछ में ब्रिजलाल ने शराब गौरव जायसवाल की बताई और बाद में गौरव ने भी शराब अपनी होना स्वीकार कर लिया। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं 34(2), 36 और 59(क) के तहत कार्रवाई की गई।

हर कार्रवाई में कहानी लगभग एक जैसी रही—एक आरोपी पकड़ा,उसने दूसरा नाम बताया और अगले दिन दूसरा आरोपी जेल में।

ऑपरेशन क्लीन या 'सीरियल ऑपरेशन'?

यदि पिछले डेढ़-दो महीने की कार्रवाई पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि ऑपरेशन क्लीन अब किसी वेब सीरीज की तरह हर सप्ताह नया एपिसोड लेकर आ रहा है। पहले वाहिद अंसारी पकड़ा गया तो मोशीम अंसारी सामने आया। फिर साहिल तिर्की से नितीश गुप्ता तक टीम पहुंची। सीतापुर में सजाद अली के बाद महबूब खान गिरफ्तार हुआ। ब्रह्मपारा में आशा पांडेय पकड़ी गई तो 24 घंटे में राजेश मंदिलवार उर्फ बुटन जेल पहुंच गया। इसके बाद अविनाश पैकरा से पूछताछ हुई तो बलरामपुर के अमर विश्वकर्मा उर्फ बिट्टू को जंगल से पकड़ लिया गया। गंगापुर में विजय गिरी के घर से 200 किलो महुआ लाहन,15 लीटर हाथ भट्ठी शराब और चलती भट्ठी बरामद हुई। और अब नुनेरा गांव में 18 पेटी मध्यप्रदेश की विदेशी शराब बरामद हो गई।

सुपरमैन की स्पीड पर कोई सवाल नहीं...लेकिन मंजिल पर जरूर है : सुपरमैन रंजीत गुप्ता की सक्रियता पर शायद ही कोई सवाल उठे। मुखबिर की सूचना मिलते ही दबिश,कुछ घंटों में गिरफ्तारी और अगले दिन न्यायिक रिमांड–यह सिलसिला लगातार जारी है। यही वजह है कि विभाग के भीतर और बाहर उन्हें 'सुपरमैन' कहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन हर सफल कार्रवाई के साथ एक नया सवाल भी जन्म ले रहा है। यदि हर आरोपी किसी दूसरे सप्लायर का नाम बता रहा है,तो क्या यह पूरी श्रृंखला केवल स्थानीय स्तर तक ही सीमित है? या फिर इसके ऊपर भी कोई ऐसा नेटवर्क है,जो हर बार जांच की पहुंच से थोड़ा आगे खड़ा दिखाई देता है?

90 प्रतिशत विक्रेता जेल में... फिर बाजार खाली क्यों नहीं?

कुछ दिन पहले स्वयं आबकारी विभाग ने दावा किया था कि अंबिकापुर के 90 प्रतिशत नशीले इंजेक्शन विक्रेता जेल जा चुके हैं।

यदि ऐसा है तो फिर समय-समय पर नए विक्रेता,नए सप्लायर और नई खेप आखिर कहां से आ रही है?

यह प्रश्न केवल विपक्ष या आम जनता का नहीं, बल्कि उन लोगों का भी है जो लगातार हो रही कार्रवाई की सराहना करते हुए चाहते हैं कि अब जांच उस स्तर तक पहुचे जहां से पूरा नेटवर्क संचालित होता है।

अब शराब भी सीमा पार से...

ताजा कार्रवाई ने एक और संकेत दिया है कि अब केवल नशीले इंजेक्शन ही नहीं,बल्कि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश से विदेशी शराब की तस्करी का नेटवर्क भी सक्रिय है। 18 पेटियों में 900 पाव शराब की बरामदगी यह बताती है कि अवैध कारोबार छोटे स्तर का नहीं था। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि इतनी बड़ी खेप सीमाएं पार कर गांव तक पहुंची कैसे? क्या केवल दो लोगों की गिरफ्तारी से पूरा मामला समाप्त मान लिया जाए या इसके पीछे मौजूद परिवहन,भंडारण और आपूर्ति नेटवर्क की भी गहराई से जांच होनी चाहिए?

चर्चा में सुपरमैन...अंबिकापुर में आजकल एक चर्चा खूब सुनाई देती है...

'सुपरमैन हर बार विलेन के गुर्गों को पकड़ लाते हैं,लेकिन फिल्म का असली विलेन अब तक इंटरवल के बाद भी स्क्रीन पर नहीं आया।' यह टिप्पणी व्यंग्य जरूर है,लेकिन इसके पीछे जनता की अपेक्षा भी छिपी है। लगातार कार्रवाई से यह साबित हुआ है कि आबकारी उड़नदस्ता सक्रिय है,लेकिन अब लोगों की नजर उस दिन पर टिकी है,जब केवल फुटकर विक्रेता या स्थानीय सप्लायर नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का संचालन करने वाले बड़े चेहरे भी कानून के शिकंजे में दिखाई देंगे। क्योंकि ऑपरेशन क्लीन की असली सफलता तब मानी जाएगी,जब हर कार्रवाई के बाद नया नाम सामने आने के बजाय पूरा नेटवर्क एक साथ ध्वस्त होता दिखाई दे।

बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश आदिवासी समाज ने एसपी कार्यालय का किया घेराव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

शहर से लगे भफौली गांव में नाबालिग आदिवासी बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर बुधवार को सर्व आदिवासी समाज का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और घेराव कर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरने पर बैठ गए। भारी बारिश के बावजूद वे अपनी मांग पर डटे रहे। जानकारी के अनुसार भफौली गांव की उपसरपंच के पति तरुण जायसवाल पर घर में काम करने वाली नाबालिग आदिवासी बालिका से दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही आरोपी फरार हो गया था और अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। आरोपी की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर आदिवासी समाज में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने में विफल रहने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन को देखते हुए एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।

पेट्रोल पंप के पैनल रूम में युवक की संदिग्ध मौत...परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था युवक,ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप...20 लाख रुपए लेकर पार्टनर बनने आया था अंबिकापुर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

शहर के रवि फ्यूल्स पेट्रोल पंप के पैनल रूम में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर मामला करंट लगने से मौत का बताया जा रहा है,लेकिन मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए ठेकेदार और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिहार के बेगूसराय निवासी 35 वर्षीय सौरभ सिंह पिता मनोज सिंह कुछ दिन पहले बेगूसराय की लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार के साथ अंबिकापुर आया था। कंपनी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों का मेंटेनेंस कार्य करती है। बताया गया कि 3 अगस्त की रात सौरभ अपने साथी शादाब के साथ रवि फ्यूल्स पेट्रोल पंप पहुंचा था। दोनों ने खाना खाने के बाद पैनल रूम में विश्राम किया। साथी शादाब ने पुलिस को बताया कि रात करीब 12 बजे वह लघुशंका के लिए उठा तो देखा कि सौरभ बिजली के पैनल से चिपका हुआ था। आशंका है कि मोबाइल चार्जिंग के दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने उठाए कई सवाल : घटना की सूचना मिलने पर मृतक के पिता मनोज सिंह और अन्य परिजन अंबिकापुर पहुंचे। उन्होंने मौत पर संदेह जताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की है। परिजनों का कहना है कि सौरभ के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं, दोनों कानों के पास करंट के निशान दिखाई दे रहे हैं और घटनास्थल पर खून के धब्बे भी मिले हैं। उनका दावा है कि केवल करंट लगने से इस तरह खून निकलना संभव नहीं है।

20 लाख रुपए लेकर आया था : मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के संचालक मनोहर सिंह और मन्नु काम दिलाने और साझेदारी का झांसा देकर उनके बेटे को अंबिकापुर लाए थे। उनका कहना है कि सौरभ करीब 20 लाख रुपए लेकर घर से निकला था और उसने परिवार को बताया था कि वह कारोबार में पार्टनर बन गया है। बाद में उसने फोन पर यह भी कहा था कि साझेदार उसे परेशान कर रहे हैं और विवाद चल रहा है।

पत्नी से कहा था...पैसा नहीं दे रहे,मारपीट करते हैं...

परिजनों के अनुसार 3 अगस्त की शाम सौरभ ने अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत की थी। उसने बताया था कि वह जल्द घर लौटेगा,लेकिन साझेदार रुपए नहीं दे रहे हैं और उसके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। अगले दिन जब पिता ने फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुई। कुछ देर बाद सूचना मिली कि सौरभ की करंट लगने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है।

महापौर ने प्रतीक्षा बस स्टैंड का किया निरीक्षण,व्यवस्थाएं सुधारने के दिए निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

महापौर मंजूषा भगत एवं निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने मंगलवार को प्रतीक्षा अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से चर्चा कर बस स्टैंड को व्यवस्थित बनाने पर सहमति बनाने की पहल की। निरीक्षण के दौरान निगम स्वामित्व की दुकानों से अवैध कब्जा हटाने, दुकानों के सामने सामान व्यवस्थित रखने,यूरिनल,टॉयलेट,नालियों व परिसर की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए वाटर कूलर,वाटर एटीएम और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया। महापौर ने वेटिंग हॉल के नवीनीकरण,शेड के नीचे हुए अतिक्रमण हटाने, रैन बसेरा को व्यवस्थित करने तथा बस स्टैंड भवन व परिसर की मरम्मत कराने पर भी जनप्रतिनिधियों,व्यापारियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। निरीक्षण के दौरान एमआईसी सदस्य, पार्षद एवं निगम के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

NEET/JEE ऑनलाइन कोचिंग सुविधा हेतु कोचिंग संस्थानों से आवेदन आमंत्रित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सरगुजा जिले के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय (जीवविज्ञान एवं गणित संकाय) में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए NEET/JEE ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न कोचिंग संस्थानों से आवेदन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं पात्र कोचिंग संस्थान अपने आवेदन प्रस्ताव 25 अगस्त 2026 तक कार्यालयीन समयावधि में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,अम्बिकापुर, सरगुजा में जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रस्ताव बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिशः जमा किया जा सकेगा। आवेदन प्रस्ताव जमा करने का पता हैकृकार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर,सरगुजा, सिटी कोतवाली थाना के सामने,गुरूनानक चौक, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़), पिन कोड-497001। आवेदन प्रस्ताव निर्धारित अंतिम तिथि को सायं 5रू30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सरगुजा संभाग के 850 तीर्थयात्री अयोध्या धाम दर्शन के लिए विशेष ट्रेन से रवाना

महापौर श्रीमती मंजूषा भगत ने हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन को किया रवाना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा संचालित श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना के अंतर्गत आज 05 अगस्त 2026 को सरगुजा संभाग के 850 तीर्थयात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। विशेष ट्रेन को महापौर,अंबिकापुर श्रीमती मंजूषा भगत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं उप संचालक, समाज कल्याण विभाग श्री व्ही.के. उके ने बताया कि जिला सरगुजा से कुल 170 तीर्थयात्री अयोध्या धाम दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। इनमें जनपद पंचायत अंबिकापुर से 18,उदयपुर से 18, लखनपुर से 18,लुण्ड्रा से 18,बतौली से 18, सीतापुर से 18 तथा मैनपाट से 18 तीर्थयात्री शामिल हैं। इसके अलावा नगर निगम अंबिकापुर से 30, नगर पंचायत लखनपुर से 07 तथा नगर पंचायत सीतापुर से 07 तीर्थयात्री यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या धाम दर्शन के लिए रवाना हुई विशेष ट्रेन 08 अगस्त 2026 को वापस लौटेगी। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। विशेष ट्रेन के प्रस्थान के अवसर पर जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह,नगर निगम अंबिकापुर के सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी, जनप्रतिनिधिगण एवं पार्षदगण उपस्थित रहे। साथ ही टूरिज्म बोर्ड सरगुजा संभाग के क्षेत्रीय अधिकारी श्री आशीष वर्मा, रेलवे एवं आईआरसीटीसी के अधिकारी-कर्मचारी तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे। श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला के दर्शन का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से श्रद्धालुओं को धार्मिक एवं आध्यात्मिक यात्रा का लाभ मिल रहा है।

ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस की सख्ती,3 वाहन चालकों पर 30 हजार का जुर्माना

दो बाइक और एक सूमो चालक शराब के नशे में वाहन चलाते मिले,न्यायालय ने प्रत्येक पर 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात शाखा ने ड्रंक एंड ड्राइव के तीन मामलों में सख्त कार्रवाई की है। शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए दो मोटरसाइकिल चालकों और एक सूमो चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया,जहां तीनों पर कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान चेकिंग के समय बाइक क्रमांक सीजी-15-डीएक्स-4819 के चालक नंदूराम सिंह (20),निवासी गंगापुर, थाना जयनगर को रोककर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई में बाइक क्रमांक सीजी-15-ईके-5839 के चालक अजय कुजूर (24), निवासी सुखरी, थाना गांधीनगर भी शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। वहीं तीसरे मामले में सूमो क्रमांक सीजी-29-एसी-1148 के चालक प्रकाश यादव (25), निवासी पोड़ी,थाना प्रतापपुर को भी ब्रेथ एनालाइजर जांच में नशे की हालत में वाहन चलाते पाया गया। तीनों चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस तरह कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। यातायात पुलिस ने लोगों से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त सहित यातायात शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही।

एनएसयूआई ने छात्रहित के मुद्दों पर कुलपति को सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने सरगुजा संभाग विश्वविद्यालय अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर छात्रहित से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण की मांग की। ज्ञापन में मुख्य वार्षिक परीक्षा 2026 के अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा के साथ विशेष परीक्षा आयोजित करने,पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना के लंबित परिणाम जारी करने तथा यूएफएम और विथहेल्ड प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने की मांग की गई। एनएसयूआई ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया जारी होने के कारण परीक्षा व परिणाम में देरी से विद्यार्थियों का पूरा शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हो सकता है। इस दौरान उपाध्यक्ष गौतम गुप्ता सहित अमन सिंह, मनीष सोनी, प्रिंस, अभिषेक और इलेश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

CMYK

16 महीने बाद तत्कालीन तहसीलदार संजय राठौर पर एफआईआर

'घटती-घटना' ने जिन सवालों को उठाया था...अब उन्हीं आरोपों की होगी आपराधिक जांच...

- खोजी खबरों से एफआईआर तक...16 महीने बाद कानून के घेरे में आए तत्कालीन तहसीलदार संजय राठौर
- जिन आरोपों पर पहले विभागीय जांच हुई,अब उन्हीं मामलों में दर्ज हुई एफआईआर
- जीवित महिला को मृत बताकर जमीन नामांतरण के आरोप में 16 महीने बाद एफआईआर,तत्कालीन तहसीलदार पर कानून का शिकंजा
- लगातार उठते रहे सवाल,16 महीने बाद दर्ज हुई एफआईआर... तत्कालीन तहसीलदार संजय राठौर पर आपराधिक जांच शुरू

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,05 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

लगभग 16 महीने तक शिकायत,जनसुनवाई, विभागीय जांच,समाचारों की श्रृंखला और प्रशासनिक इंतजार के बाद आखिरकार सूरजपुर जिले के तत्कालीन भैयाथान तहसीलदार संजय कुमार राठौर के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हो गया है,थाना झिलमिली में दर्ज एफआईआर क्रमांक 0185/2026 केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं है,बल्कि उस पूरे घटनाक्रम का अगला चरण है जिसकी शुरुआत वर्ष 2025 में हुई थी। उस समय एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसे जीवित रहते हुए सरकारी अभिलेखों में मृत दर्शाकर उसकी कृषि भूमि का नामांतरण कर दिया गया, कथित रूप से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया गया और बाद में उसी भूमि का विक्रय भी कर दिया गया,इस शिकायत ने राजस्व विभाग, प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे,इसी दौरान दैनिक घटती-घटना ने इस पूरे मामले को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया। समाचार-पत्र ने केवल एक शिकायत प्रकाशित कर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं मानी, बल्कि कई महीनों तक अलग-अलग तथ्यों,दस्तावेजों और शिकायतों के आधार पर लगातार सवाल उठाए कि आखिर शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी जीवित व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर भूमि का नामांतरण संभव है? यदि नहीं,तो यह कैसे हुआ? यदि हुआ, तो जिम्मेदार कौन है? आज लगभग 16 महीने बाद जब इसी मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है,तब यह मामला फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।

पत्नी के नाम जमीन खरीदने का मामला भी बना चर्चा का विषय-इसी बीच संजय राठौर से जुड़ा एक और विवाद सामने आया, शिकायतों में आरोप लगाया गया कि एक विवादित भूमि प्रकरण के निराकरण के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदी, इसी विषय पर दैनिक घटती-घटना ने विस्तृत समाचार प्रकाशित करते हुए सवाल उठाया था कि क्या कोई अधिकारी जिस क्षेत्र में विवादों का निराकरण कर रहा हो, उसी क्षेत्र में उसके परिवार द्वारा भूमि खरीदे जाने की स्वतंत्र जांच नहीं होनी चाहिए? समाचार पत्र ने यह भी प्रश्न उठाया कि यदि ऐसा हुआ है तो क्या इससे हितों के टकराव की स्थिति बनती है? यह मामला भी विभागीय जांच का हिस्सा बना।

लगातार प्रकाशित हुई थीं खोजी खबरें-दैनिक घटती-घटना ने इस पूरे प्रकरण में कई प्रमुख समाचार प्रकाशित किए,जिनमें प्रमुख थे—तहसीलदार पर लगे गंभीर आरोप,क्या कलेक्टर सूरजपुर उन्हें तहसील कार्यालय से पृथक कर जांच करवाएंगे? क्या तहसीलदार संजय राठौर किसी के मामले का निराकरण कर प्रतिफल स्वरूप अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदते हैं? 25 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, जनदर्शन शिकायत पर प्रशासन खामोश क्यों? भैयाथान तहसीलदार मामले में दैनिक घटती-घटना की खबर का बड़ा असर, संभागायुक्त ने किया निलंबित, इन समाचारों के माध्यम से लगातार प्रशासन का ध्यान इस प्रकरण की ओर आकर्षित किया गया।

एफआईआर में किन-किन लोगों के नाम-दर्ज एफआईआर के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार संजय कुमार राठौर के साथ अन्य व्यक्तियों को भी आरोपित बनाया गया है, पुलिस अब सभी आरोपितों की भूमिका की जांच करेगी।

अब किन बिंदुओं पर होगी पुलिस जांच? पुलिस विवेचना के दौरान निम्न प्रमुख बिंदुओं की जांच करेगी—

- मृत्यु प्रमाण पत्र वास्तविक था या कथित रूप से फर्जी?
- प्रमाण पत्र किसने जारी किया?
- नामांतरण आदेश किन दस्तावेजों के आधार पर पारित हुआ?
- दस्तावेजों का सत्यापन हुआ था या नहीं?
- भूमि विक्रय की प्रक्रिया वैधानिक थी या नहीं?
- राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन किस स्तर पर किया गया?

क्या पूरी प्रक्रिया में आपराधिक षड्यंत्र था?

सबसे बड़ा सवाल—16 महीने क्यों लगे?-इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि शिकायतें वर्ष 2025 में सामने आ गई थीं,विभागीय जांच भी शुरू हो गई थी, निलंबन भी हो गया था और समाचार लगातार प्रकाशित हो रहे थे,तो एफआईआर दर्ज होने में लगभग 16 महीने क्यों लग गए? क्या दस्तावेजों के सत्यापन में समय लगा? क्या विभागीय जांच पूरी होने की प्रतीक्षा की गई? क्या पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य बाद में मिले? या फिर प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने में देरी हुई? इन प्रश्नों का उत्तर फिलहाल आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

अब विभागीय जांच का क्या होगा?-एफआईआर दर्ज होने के बाद अब विभागीय जांच भी महत्वपूर्ण हो गई है,यदि पुलिस विवेचना में आरोप पुष्ट होते हैं तो विभागीय कार्रवाई का स्वरूप भी बदल सकता है, प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा है कि अब लंबित विभागीय जांच को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

राजस्व व्यवस्था की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न-यह मामला केवल एक अधिकारी का नहीं बल्कि पूरी राजस्व व्यवस्था का भी परीक्षण है,यदि किसी जीवित महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्शाकर नामांतरण संभव हुआ,तो यह जांच का विषय है कि-राजस्व रिकॉर्ड का सत्यापन कैसे हुआ? तहसील स्तर पर दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं हुई? पंजीयन कार्यालय ने किन दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री की? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था में बदलाव होगा?

2025 में शुरू हुआ था पूरा घटनाक्रम

वर्ष 2025 में तत्कालीन भैयाथान तहसीलदार संजय राठौर के विरुद्ध पहली बार शिकायत सामने आई, शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि वह पूरी तरह जीवित हैं, लेकिन राजस्व अभिलेखों में उन्हें मृत दर्शाकर उनकी कृषि भूमि का नामांतरण कर दिया गया,शिकायत के अनुसार कथित रूप से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, उसी के आधार पर नामांतरण आदेश पारित हुआ और बाद में भूमि का पंजीकृत विक्रय भी कर दिया गया, यह आरोप सामने आने के बाद मामला केवल एक निजी भूमि विवाद नहीं रह गया,बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का विषय बन गया।

जब अधिकांश लोग चुप थे,तब लगातार सवाल उठा रहा था 'दैनिक घटती-घटना'

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि जब शिकायत केवल फाइलों में सीमित थी, तब दैनिक घटती-घटना ने लगातार इस विषय को प्रमुखता से प्रकाशित किया,समाचार पत्र ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए क्या तहसीलदार कार्यालय में बिना सत्यापन के नामांतरण हो सकता है? यदि महिला जीवित थी तो मृत्यु प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी हुआ? नामांतरण से पहले स्थानीय जांच हुई थी या नहीं? क्या शिकायतों को जानबूझकर दबाया जा रहा है? क्या संबंधित अधिकारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? समाचारों के माध्यम से यह भी मांग की गई कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

विभागीय जांच हुई,निलंबन भी हुआ

लगातार शिकायतों और समाचारों के बाद सरगुजा संभाग स्तर पर विभागीय जांच प्रारंभ हुई, प्राथमिक जांच में कुछ आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर पाए जाने के बाद तत्कालीन तहसीलदार संजय राठौर को निलंबित किया गया,यह कार्रवाई इस बात का संकेत थी कि प्रशासन ने शिकायतों को गंभीर माना, हालांकि विभागीय जांच अभी भी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है।

फिर कोरिया जिले में हुई पदस्थापना

निलंबन के बाद संजय राठौर की पुनः पदस्थापना की गई और बाद में उनका स्थानांतरण कोरिया जिले की बचरापोड़ी तहसील में कर दिया गया,इस दौरान शिकायतकर्ता लगातार पुलिस कार्रवाई की मांग करती रहीं, सवाल यह भी उठता रहा कि यदि विभागीय जांच हो चुकी है और अधिकारी पर कार्रवाई भी हुई है,तो आपराधिक मामला दर्ज होने में इतनी देरी क्यों हुई?

16 महीने बाद अब दर्ज हुई एफआईआर

आखिरकार 03 अगस्त 2026 को झिलमिली थाना में एफआईआर क्रमांक 0185/2026 दर्ज कर ली गई,एफआईआर के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार संजय कुमार राठौर सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध बीएनएस की कई धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है,एफआईआर में कथित रूप से आरोप लगाया गया है कि जीवित महिला को मृत दर्शाया गया,कथित फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया,उसी के आधार पर नामांतरण कराया गया,बाद में भूमि का विक्रय किया गया, पूरी प्रक्रिया कथित रूप से सुनियोजित तरीके से संपन्न हुई।

क्या 'घटती-घटना' की पड़ताल सही दिशा में थी?

यह कहना जल्दबाजी होगी कि समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित प्रत्येक आरोप सही सिद्ध हो गया है,क्योंकि इसकी पुष्टि न्यायालय और जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन यह तथ्य जरूर सामने है कि जिन शिकायतों और आरोपों को लेकर वर्ष 2025 से लगातार समाचार प्रकाशित किए गए, उसी प्रकरण में अब पुलिस ने औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर आपराधिक जांच शुरू कर दी है, इससे खोजी पत्रकारिता की भूमिका और सार्वजनिक शिकायतों को लगातार सामने लाने के महत्व पर भी चर्चा तेज हो गई है।

अब आगे क्या होगा?

अब पुलिस सभी दस्तावेजों का परीक्षण करेगी,गवाहों के बयान दर्ज करेगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी,यदि जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा,यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो जांच एजेंसी अपनी अंतिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी, इसी के साथ विभागीय जांच भी अपने अंतिम चरण में पहुंच सकती है।

'परवाज' कार्यक्रम में छात्राओं से खुला संवाद,तस्करी,नशा और मानसिक स्वास्थ्य पर किया जागरूक

सेवा किटी समूह ने सरगावां स्कूल की छात्राओं को शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का दिया संदेश, निःशुल्क सेनेटरी पैड भी वितरित किए...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,05 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

सेवा किटी समूह द्वारा संचालित 'परवाज' कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरगावां में कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं के साथ समसामयिक एवं संवेदनशील सामाजिक विषयों पर संवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवा किटी समूह की संस्थापिका वंदना दत्ता एवं सदस्य दीपमाला सिंह ने छात्राओं से खुलकर चर्चा करते हुए उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान पर मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं की तस्करी, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति,अवसाद,तनाव,मानसिक स्वास्थ्य तथा संस्कारयुक्त जीवनशैली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। वंदना दत्ता ने कहा कि परिवार और विद्यालय में अनुशासन एवं मर्यादा का पालन प्रत्येक छात्रा का दायित्व है। उन्होंने नशामुक्त समाज के निर्माण में महिलाओं और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि'बेटियां परिवार के लिए सीढ़ी नहीं, बल्कि उसका मजबूत सम्बल बनें। 'दीपमाला सिंह ने बताया कि सेवा किटी समूह जरूरतमंद बालिकाओं को शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराएगा। साथ ही शासन द्वारा छात्राओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं को निःशुल्क सेनेटरी पैड वितरित किए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिंह सहित अध्यापिका सुजाता सिंह,रेखा सिंह एवं पूर्णिमा सिंह ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालय परिवार ने सेवा किटी समूह के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे छात्राओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में उपयोगी पहल बताया।

CMYK

विकास कॉरिडोर या कमीशन कॉरिडोर?

7.18 करोड़ की सड़क, 5 महीने की समय-सीमा, एक साल बाद भी अधूरी!

18.18% कम दर पर ठेका, गुणवत्ता पर सवाल, कछुए की चाल से निर्माण

गंगोटी से शिवपुर नवापारा सड़क
लंबाई - 5.10 किमी.

कार्यादेश जारी
30 जून 2025

समय-सीमा
5 माह (नवंबर 2025 तक पूरा होना था)

वर्तमाना स्थिति
एक साल बाद भी लगभग 40% कार्य

अनुबंध राशि
₹5.8781 करोड़
(S.O.R. से 18.18% कम)

सवाल ये है...
कम गुणवता, देरी और विभाग की चुप्पी
आखिर कब तक?

ठेकेदार
जवाहरलाल गुप्ता

पीडब्ल्यूडी की मजबूत सड़क बन रही है या ठेकेदार की मनचाही कमाई का रास्ता?

क्या भ्रष्टाचार का नया कॉरिडोर बन रही है 7.18 करोड़ की गंगोटी-शिवपुर सड़क?

5 महीने की समय-सीमा,एक साल बाद भी अधूरी 7.18 करोड़ की सड़क! पीडब्ल्यूडी की मजबूत सड़क बन रही है या ठेकेदार की मनचाही कमाई का रास्ता?

18.18% कम दर पर मिला ठेका, गुणवत्ता पर उठे सवाल, एस्टीमेट से अलग निर्माण का आरोप, विभाग की चुप्पी से बढ़ी शंकाएं

30 जून 2025 को जारी हुआ था कार्यादेश, नवंबर 2025 तक पूरा होना था कार्य, अब एक साल से अधिक समय बाद भी लगभग 40 प्रतिशत निर्माण ही दिखाई देने का दावा

ओंकार पाण्डेय

सूरजपुर,05 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा देने का दावा कर रही है, लेकिन सूरजपुर जिले की गंगोटी से शिवपुर नवापारा तक 5.10 किलोमीटर सड़क निर्माण परियोजना अब विकास से ज्यादा सवालों का विषय बन गई है, लगभग 7.18 करोड़ रुपये की इस परियोजना में देरी, निर्माण की गुणवत्ता और विभागीय निगरानी तीनों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 30 जून 2025 को इस सड़क का कार्यादेश जारी किया, कार्य मे. जवाहरलाल गुप्ता को दिया गया, अनुबंध के अनुसार कार्य 5 माह में पूरा होना था तथा कार्य अवधि में वर्षा ऋतु भी शामिल थी, अर्थात सामान्य परिस्थितियों में यह सड़क नवंबर 2025 तक तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज, कार्यादेश जारी होने के एक वर्ष से अधिक समय बाद भी सड़क पूर्ण नहीं हो सकी, स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य अभी भी लगभग 40 प्रतिशत के आसपास ही दिखाई देता है, यदि यह स्थिति वास्तविक है, तो यह केवल निर्माण में देरी नहीं बल्कि अनुबंध की शर्तों के पालन पर भी गंभीर प्रश्न है।

18.18 प्रतिशत कम दर पर ठेका,क्या यहीं से शुरू हुई गुणवत्ता की कहानी?-

इस कार्य की कुल स्वीकृत लागत 7.1842 करोड़ है, दस्तावेजों के अनुसार ठेका एसओआर से 18.18 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत किया गया, जिसके कारण अनुबंध राशि घटकर लगभग 5.8781 करोड़ रह गई, कम दर पर कार्य लेना सरकारी निविदा प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब वही कार्य निर्धारित समय पर पूरा न हो, निर्माण की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठने लगें और जमीनी स्थिति एस्टीमेट से मेल न खाती दिखाई दे, तब यह जांच का विषय बन जाता है, स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में कई स्थानों पर बेस कमजोर दिखाई दे रही है, कहीं मोटाई कम नजर आती है तो कहीं निर्माण की गति इतनी धीमी है कि पूरी परियोजना पर ही प्रश्नचिह्न लग गया है।

कछुए की चाल से निर्माण, आखिर जिम्मेदार कौन?-

निर्माण कार्य में सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल ठेकेदार की नहीं होती, उप अभियंता, सहायक अभियंता,कार्यपालन अभियंता सहित पूरा तकनीकी अमला गुणवत्ता की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है, यदि सड़क समय पर नहीं बन रही, यदि गुणवत्ता पर सवाल हैं और यदि निर्माण धीमी गति से चल रहा है, तो फिर विभागीय निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

क्या ठेकेदार इतना 'बहेता' है कि विभाग ने आंखें मूंद ली हैं?-

क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि समय-सीमा समाप्त होने के महीनों बाद भी न तो कोई कठोर कार्रवाई दिखाई देती है और न ही सार्वजनिक रूप से किसी प्रकार की जवाबदेही तय होती है, यही वजह है कि लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विभाग ने गुणवत्ता देखने वाला चश्मा उतार दिया है? क्या अधिकारियों ने केवल प्रगति रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया है? या फिर सब कुछ ठीक मान लिया गया है? इन सवालों के ठोस उत्तर केवल विभाग ही दे सकता है।

वर्क ऑर्डर क्या कहता है?-

कार्यादेश के अनुसार यह केवल डामरीकरण का काम नहीं है बल्कि संपूर्ण सड़क अवसंरचना विकसित की जानी है, दस्तावेजों में शामिल प्रमुख कार्यों में–5.10 किलोमीटर सड़क निर्माण, भूमि समतलीकरण एवं एम्बैंकमेंट, प्राइम कोट, टैक कोट, बिटुमिनस मैकडम, दोनों ओर शोल्डर, लगभग 2182 मीटर आरसीसी नाली, पुलिया एवं कलवर्ट निर्माण, 600 मिमी व्यास के 110 मीटर आरसीसी पाइप कलवर्ट, आरसीसी संरचनाएं एवं अन्य तकनीकी कार्य शामिल हैं, यानी यह केवल सड़क नहीं बल्कि पूर्ण सड़क परियोजना है।

क्या एस्टीमेट के अनुसार हो रहा है निर्माण?-

यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ग्रामीणों का आरोप है कि कई स्थानों पर कार्य तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं दिख रहा, यदि ऐसा है तो विभाग को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सड़क की प्रत्येक लेयर निर्धारित मोटाई के अनुसार बिछाई जा रही है? क्या निर्धारित गुणवत्ता की गिट्टी और सामग्री का उपयोग हो रहा है? क्या रोलिंग निर्धारित मानकों के अनुसार की जा रही है? क्या आरसीसी नालियां एवं पुलिया स्वीकृत ड्राइंग के अनुरूप बन रही हैं? इन सवालों का उत्तर अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

60 महीने की वारंटी का मतलब क्या खराब गुणवत्ता की छूट है?

कार्यादेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कार्य पूर्ण होने के बाद 60 माह की परफॉर्मेंस गारंटी रहेगी, लेकिन क्या इस वारंटी का अर्थ यह है कि निर्माण के समय गुणवत्ता से समझौता कर लिया जाए? बिल्कुल नहीं, परफॉर्मेंस गारंटी का उद्देश्य यह है कि यदि बाद में कोई तकनीकी दोष सामने आए तो ठेकेदार उसे अपने खर्च पर सुधारे। इसका अर्थ यह नहीं कि निर्माण के दौरान तकनीकी मानकों को नजरअंदाज किया जाए, यदि बेस कमजोर होगी, यदि मोटाई कम होगी, यदि सामग्री मानक से कम होगी, तो सड़क की आयु प्रारंभ से ही प्रभावित होगी।

दो बार खबर प्रकाशित हुई, फिर भी व्यवस्था क्यों नहीं जागी?

इस सड़क निर्माण को लेकर पहले भी समाचार प्रकाशित किए जा चुके हैं। निर्माण की धीमी गति, गुणवत्ता पर उठते सवाल और जमीनी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं, इसके बावजूद यदि कार्य की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई देता, तो यह भी सवाल उठना स्वाभाविक है कि–क्या विभाग ने गुणवत्ता परीक्षण कराया? क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई गई? क्या विलंब पर नोटिस जारी किया गया? क्या अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई हुई? यदि हुई तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं है?

क्या पीडब्ल्यूडी ने तकनीकी जांच कराई?- इतने बड़े कार्य में सामान्यत...

फील्ड टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट,सामग्री परीक्षण,मोटाई की जांच,लेयर माप,क्यूब टेस्ट,बिटुमिनस गुणवत्ता परीक्षण जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं,यदि ये परीक्षण हुए हैं तो उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि लोगों के मन में उठ रहे संदेह समाप्त हो सकें।

करोड़ों की सड़क,लेकिन जनता अब जवाब चाहती है...

यह सड़क केवल गंगोटी और शिवपुर नवापारा को जोड़ने वाली सड़क नहीं है,यह ग्रामीणों की उम्मीदों, सरकारी धन और विभागीय जवाबदेही की परीक्षा भी है,करीब 7.18 करोड़ रुपये खर्च होने हैं,इसलिए जनता यह जानना चाहती है सड़क समय पर क्यों नहीं बनी? निर्माण की गति इतनी धीमी क्यों है? क्या एस्टीमेट के अनुसार कार्य हो रहा है? गुणवत्ता की जांच किसने की? विलंब के लिए जिम्मेदार कौन है? यदि अनुबंध का उल्लंघन हुआ है तो क्या कार्रवाई की गई?

अब विभाग को देना होगा स्पष्ट जवाब...

जब करोड़ों रुपये जनता के कर से खर्च हो रहे हों,तब केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि '60 महीने की वारंटी है,बाद में ठीक करा देंगे,जनता की अपेक्षा यह है कि सड़क पहली बार में ही तकनीकी मानकों के अनुरूप बने,समय पर बने और वर्षों तक टिकाऊ रहे,अब आवश्यकता है कि पीडब्ल्यूडी इस पूरे मामले में स्वतंत्र तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण,एस्टीमेट के अनुरूप कार्य का सत्यापन,विलंब की जवाबदेही तय करने तथा पूरी परियोजना की सार्वजनिक समीक्षा कराए,यदि सब कुछ मानकों के अनुरूप है तो विभाग को प्रमाण प्रस्तुत कर जनता का विश्वास मजबूत करना चाहिए, और यदि कहीं कमी है तो उसे स्वीकार कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि विकास केवल भूमिपूजन, नारियल फोड़ने और उद्घाटन की तस्वीरों से नहीं, बल्कि समय पर बनी टिकाऊ सड़क से साबित होता है।

सैनिक स्कूल अंबिकापुर में अंतर-हाउस बास्केट बॉल चैम्पियनशिप का हुआ आयोजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,05 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

सैनिक स्कूल अंबिकापुर में अंतर-हाउस बास्केट बॉल चैम्पियनशिप 2026-27 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विद्यालय के विभिन्न हाउसों के कैडेटों ने उत्साह और खेल भावना के साथ भाग लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान सीनियर,जूनियर और बालिका वर्ग के बीच कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। सभी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिता के परिणामों में सीनियर वर्ग में मानेकशॉ हाउस ने विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया, जबकि जूनियर वर्ग में पिनाका हाउस ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसी प्रकार बालिका वर्ग में करियप्पा हाउस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया।

समापन समारोह में विद्यालय के प्राचार्य कर्नल राजेश बैंदा ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और ट्रॉफियां प्रदान कीं तथा सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास करते हैं तथा उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। यह प्रतियोगिता कैडेटों के सर्वांगीण विकास और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल साबित हुई।

रजत पदक जीतकर ज्ञानेश्वरी यादव ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का गौरव, भाजयुमो ने दी बधाई

जिला अध्यक्ष देव गुप्ता बोले...दृढ़ इच्छाशक्ति,अनुशासन और कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं,सरकार की खेल नीति से युवाओं को मिल रहा नया अवसर...

-संवाददाता-
सूरजपुर,05 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिला अध्यक्ष देव गुप्ता ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल-2026 की महिला 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल एक खिलाड़ी की सफलता नहीं,बल्कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प का सम्मान है। देव गुप्ता ने कहा कि अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीतना ज्ञानेश्वरी यादव की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है, उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने यह साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और समर्पण के साथ निरंतर प्रयास किए जाएं, तो कोई भी मंजिल

कठिन नहीं होती, उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा ज्ञानेश्वरी यादव को 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति देने की घोषणा प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक निर्णय है, भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करा रही है, जिससे युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी की सफलता विशेष रूप से प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उन्हें खेलों में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगी, देव गुप्ता ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, खेलों के क्षेत्र में भी महिलाओं को बेहतर अवसर, संसाधन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी ओलंपिक,राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकें, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ज्ञानेश्वरी यादव भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाती रहेंगी।

सावन में स्वर्ग-सी निखरी 'बालमगढ़ी'

कोरिया का वह अनदेखा प्राकृतिक स्वर्ग, जहाँ बादलों की ओढ़नी ओढ़कर सोती हैं पहाड़ियां और हर सांस में बस जाती है जंगल की खुशबू

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की गोद में बसी प्रकृति की अनुपम धरोहर

बादलों की ओढ़नी ओढ़े पहाड़,हरियाली की चादर और प्रकृति का अनुपम संसार

कोरिया का वह अनदेखा प्राकृतिक स्वर्ग,जहाँ हर सांस में बस जाती है जंगल की खुशबू और हर दृश्य बन जाता है जीवन भर की याद

राजन पाण्डेय

कोरिया/सोनहत,05 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सावन का महीना आते ही प्रकृति मानो स्वयं अपने सबसे सुंदर रूप में धरती पर उतर आती है, पर्वतों पर तैरते बादल,वर्षा से धुले जंगल, घाटियों में उतरती धुंध,कल-कल बहते जलस्रोत और दूर-दूर तक फैली हरियाली ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे देखकर लगता है कि धरती ने स्वयं हरे रंग का परिधान पहन लिया हो, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के घने वनांचल के बीच स्थित बालमगढ़ी ऐसा ही एक प्राकृतिक स्थल है, जो सावन के दिनों में किसी स्वर्ग से कम प्रतीत नहीं होता, यहाँ पहुँचते ही शहरों का शोर, भागदौड़ और तनाव मानो पीछे छूट जाता है, हवा में घुली मिट्टी की सोंधी खुशबू, पक्षियों का मधुर कलरव और पहाड़ों से टकराकर लौटती ठंडी हवाएँ हर आगंतुक को प्रकृति के और करीब ले आती हैं।

जहाँ बादल उतर आते हैं धरती पर...

बालमगढ़ी की सबसे बड़ी पहचान इसकी विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ और गहरी घाटियाँ हैं, मानसून के दौरान घने बादल पहाड़ों को इस तरह ढक लेते हैं कि पूरा क्षेत्र धुंध की सफेद चादर में खो जाता है,कई बार बादल इतने नीचे उतर आते हैं कि ऐसा महसूस होता है मानो वे पहाड़ियों से बातें कर रहे हों, व्यू पॉइंट से नीचे देखने पर हरियाली की अथाह गहराई और बादलों की परतें किसी चलचित्र जैसा दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जब सूरज की किरणें बादलों के बीच से निकलकर घाटियों पर पड़ती हैं तो पूरा क्षेत्र सुनहरी आभा से जगमगा उठता है।

हरियाली का अथाह समुद्र

सावन की वर्षा ने बालमगढ़ी के जंगलों को नया जीवन दे दिया है, वर्षों पुराने साल,सागौन, बाँस,अर्जुन,जामुन और अनेक औषधीय पौधे वर्षा के जल से धुलकर और अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं, पेड़ों की शाखाओं पर चमकती वर्षा की बूंदें मोतियों जैसी प्रतीत होती हैं, जंगल की मिट्टी से उठती भीनी सुगंध वातावरण को इतना शुद्ध बना देती है कि हर सांस ताजगी का एहसास कराती है,दूर तक फैली हरियाली देखकर लगता है मानो प्रकृति ने अपने रंगों का सबसे सुंदर कैनवास यहीं तैयार किया हो।

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता का अनमोल खजाना

बालमगढ़ी केवल प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र ही नहीं, बल्कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जैव विविधता का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है,यह क्षेत्र अनेक वन्यजीवों, दुर्लभ पक्षियों,तितलियों और औषधीय वनस्पतियों का प्राकृतिक आवास है,वर्षा ऋतु में जंगलों की गतिविधियाँ और भी बढ़ जाती हैं,सुबह के समय पक्षियों का सामूहिक कलरव पूरे वातावरण को जीवंत बना देता है, वन विशेषज्ञों के अनुसार यह क्षेत्र पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक धरोहर है।

घाटियों में उतरती हरियाली और बहते जलस्रोत

पहाड़ियों की तलहटी में फैले खेत सावन में हरे मखमली कालीन जैसे दिखाई देते हैं,ऊँचाइयों से उतरते छोटे-छोटे बरसाती नाले खेतों के बीच अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं,कई स्थानों पर प्राकृतिक झरने और जलधाराएँ पूरे वातावरण को संगीत से भर देती हैं,ऊँचे स्थान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि धरती पर किसी कलाकार ने विभिन्न रंगों की विशाल चित्रकला उकेर दी हो।

प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग–यदि किसी को प्रकृति की फोटोग्राफी पसंद है तो बालमगढ़ी उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं, सुबह की धुंध, बादलों से झांकती पर्वत चोटियाँ, वर्षा से भीगे वृक्ष, हरियाली में उड़ती तितलियाँ और घाटियों में उतरती सूर्य की किरणें हर पल नया दृश्य प्रस्तुत करती हैं, मानसून में यहाँ मौसम कुछ ही मिनटों में बदल जाता है, जिससे हर तस्वीर अलग और अनोखी बनती है।

शांति की तलाश करने वालों के लिए प्राकृतिक आश्रम–आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक शांति मिलना कठिन होता जा रहा है, ऐसे समय में बालमगढ़ी सुकून की तलाश करने वालों के लिए आदर्श स्थान बनकर सामने आता है, यहाँ न वाहनों का शोर है और न ही शहरों की भागदौड़, केवल हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज,झरनों की कल-कल और बादलों की गूंज सुनाई देती है, यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर पर्यटक कुछ समय के लिए स्वयं को प्रकृति का हिस्सा महसूस करने लगता है।

रोमांच प्रेमियों के लिए भी विशेष आकर्षण–बालमगढ़ी केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि साहसिक पर्यटन की भी असीम संभावनाएँ समेटे हुए है, यहाँ ट्रेकिंग, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, मानसून फोटोग्राफी, पर्वतीय दृश्यावलोकन तथा ग्रामीण पर्यटन जैसी गतिविधियाँ आसानी से विकसित की जा सकती हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहाँ बुनियादी पर्यटन सुविधाओं का संतुलित विकास किया जाए तो यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख ईको-टूरिज्म केंद्र बन सकता है।

हसदेव उद्गम स्थल से दिखता है प्रकृति का अद्भुत दृश्य

हसदेव नदी के उद्गम स्थल से बालमगढ़ी की वादियाँ और भी आकर्षक दिखाई देती हैं,सावन के मौसम में बादलों से घिरी पर्वत श्रृंखलाएँ,धुंध से ढकी घाटियाँ और दूर तक फैली हरियाली ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती हैं जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर-दूर से पहुँच रहे हैं,इन दिनों बड़ी संख्या में महिलाएँ एवं परिवार यहाँ पहुँचकर मानसून की प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे हैं। पहाड़ियों की ओर इशारा करती उत्साहित निगाहें और बादलों से घिरे दृश्य इस स्थान की लोकप्रियता को और बढ़ा रहे हैं।

ग्रामीण संस्कृति और प्रकृति का अनूठा संगम

बालमगढ़ी के आसपास बसे ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है,सावन में खेतों में काम करते किसान, हरियाली से घिरे गाँव, पारंपरिक जीवनशैली और वन आधारित संस्कृति यहाँ आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण भारत की सहज सुंदरता से परिचित कराती है, यह केवल प्राकृतिक पर्यटन नहीं,बल्कि स्थानीय संस्कृति को समझने का भी अवसर है।

पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी जिम्मेदारी

बालमगढ़ी अत्यंत संवेदनशील वन क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ आने वाले प्रत्येक पर्यटक की जिम्मेदारी है कि वह प्रकृति की इस धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करे,पर्यटकों से अपील की जाती है कि वे प्लास्टिक और अन्य कचरा जंगल में न फैलाएँ,वन्यजीवों को परेशान न करें,निर्धारित मार्गों से ही भ्रमण करें तथा वन विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करें, प्राकृतिक धरोहर तभी सुरक्षित रह सकती है जब पर्यटन और संरक्षण साथ-साथ चलें।

ईको-टूरिज्म की अपार संभावनाएँ

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि बालमगढ़ी में ईको-टूरिज्म की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं, यदि यहाँ व्यू-पॉइंट,सुरक्षित ट्रेकिंग मार्ग, सूचना केंद्र,पर्यावरण अनुकूल विश्राम स्थल,प्रशिक्षित गाइड और मूलभूत सुविधाएँ विकसित की जाएँ तो यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना सकता है,इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रकृति संरक्षण को भी नई दिशा मिलेगी।

बालमगढ़ी: जहाँ प्रकृति स्वयं कविता बन जाती है...

सावन के दिनों में बालमगढ़ी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति का जीवंत उत्सव बन जाती है, बादलों से लिपटी पहाड़ियाँ,धुंध में खोती घाटियाँ,वर्षा से धुले जंगल, झरनों की मधुर ध्वनि और असीम हरियाली हर आगंतुक को यह एहसास कराती है कि प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य अभी भी हमारे बीच सुरक्षित है,जो लोग शहरों के शोर से दूर कुछ पल सुकून चाहते हैं,जिन्हें कैमरे में प्रकृति के अनमोल क्षण कैद करना पसंद है,या जो केवल खुली हवा में जीवन का वास्तविक आनंद महसूस करना चाहते हैं— उनके लिए बालमगढ़ी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं,बल्कि आत्मा को तृप्त करने वाला अनुभव है,सावन की हर बूंद यहाँ केवल धरती को नहीं,बल्कि मन और आत्मा को भी हरियाली से भर देती है।

संत रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश सहित ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का सर्व रविदास समाज ने जताया आभार

-संवाददाता-

कोरिया,05 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सर्व रविदास समाज छत्तीसगढ़ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक लाल कुर्रे ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर की गई ऐतिहासिक घोषणाओं का स्वागत करते हुए उन्हें समाज के सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। अशोक लाल कुर्रे ने बताया कि 4 अगस्त 2026 को रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित संत रविदास जयंती समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं,जिनका सर्व रविदास समाज ने हर्ष के साथ स्वागत किया है,मुख्यमंत्री द्वारा घोषित प्रमुख निर्णयों में माघ पूर्णिमा पर संत रविदास जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश,संत रविदास के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार की स्थापना,राज्य स्थापना दिवस पर इस पुरस्कार का वितरण,छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में संत रविदास के संदेश का अंकन,नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नाम संत गुरु रविदास के नाम पर रखने तथा संत रविदास जयंती के दिन मांस एवं मदिरा की दुकानों को बंद रखने की घोषणा शामिल है,कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक लाल कुर्रे ने कहा कि मुख्यमंत्री के इन निर्णयों से संत गुरु रविदास के 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' के संदेश को नई ऊर्जा मिलेगी तथा समाज में समरसता, समानता,शिक्षा और सामाजिक सद्भाव की भावना को मजबूती मिलेगी,उन्होंने कहा कि ये घोषणाएं केवल रविदास समाज के सम्मान तक सीमित नहीं हैं,बल्कि छत्तीसगढ़ की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने वाली ऐतिहासिक पहल हैं,उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से आने वाली पीढ़ियों को संत रविदास के विचारों और आदर्शों से प्रेरणा मिलेगी तथा समाज में समानता और भाईचारे का वातावरण और मजबूत होगा,अंत में सर्व रविदास समाज छत्तीसगढ़ की ओर से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक लाल कुर्रे ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज उनके इस दूरदर्शी एवं समाजहितैषी निर्णयों के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा।

अंधेरे में डूबा मनेंद्रगढ़,सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक...कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बंद स्ट्रीट लाइटों को तत्काल चालू करने और आवारा मवेशियों को कंजी हाउस/गौठान भेजने की मांग,कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

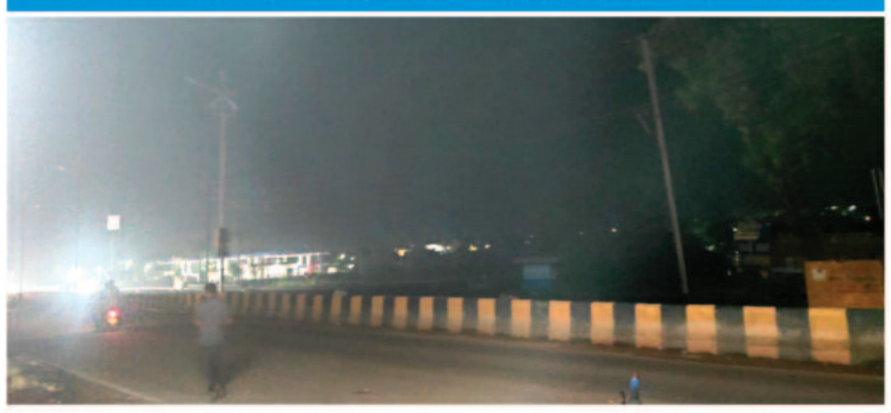

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,05 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शहर में नागरिक सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सौरव मिश्रा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल चालू कराने तथा सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को हटाने की मांग की गई, कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित में आंदोलन किया जाएगा।

शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाता है शहर

ज्ञापन में बताया गया कि नगर के अधिकांश वार्डों,मुख्य बाजार,खेड़िया तिराहा से पीडब्ल्यूडी चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर लंबे समय से स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, इसके कारण शाम होते ही सड़कें अंधेरे में डूब जाती हैं, इससे महिलाओं,विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ने की आशंका भी बनी रहती है।

करोड़ों खर्च, फिर भी नहीं मिल रही सुविधा

कांग्रेस का कहना है कि नगर पालिका द्वारा स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन समय पर रखरखाव और मरम्मत नहीं होने से जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है और नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

आवारा पशु बन रहे दुर्घटनाओं का कारण

ज्ञापन में शहर की दूसरी बड़ी समस्या आवारा पशुओं को बताया गया है,मुख्य बाजार,बस स्टैंड, खेड़िया तिराहा,पीडब्ल्यूडी चौक सहित कई व्यस्त मार्गों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, इससे दोपहिया वाहन चालकों,स्कूली बच्चों,बुजुर्गों और पैदल राहगीरों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा लगातार बना रहता है,कांग्रेस का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो भविष्य में कोई बड़ी जनहानि हो सकती है।

कंजी हाउस और गौठान भेजने की मांग

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने प्रशासन से मांग की है कि नगर पालिका विशेष अभियान चलाकर सभी आवारा पशुओं को पकड़कर कंजी हाउस अथवा गौठान में सुरक्षित भेजे, साथ ही शहर की सभी बंद स्ट्रीट लाइटों की तत्काल मरम्मत कर उन्हें चालू कराया जाए ताकि नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन

कांग्रेस ने कहा कि पार्टी हमेशा जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी, यदि प्रशासन ने शीघ्र प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो जनभावनाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस ने जिला प्रशासन से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दोनों समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है।

C M Y K

किंग के सेट से लीक हुआ शाहरुख खान का खूंखार लुक

ताबड़तोड़ एक्शन से सिनेमाघरों में मचाएंगे गदर

शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग के सेट से उनका एक एक्शन लुक लीक हो गया है,जो बेहद जबरदस्त लग रहा है।

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म किंग की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। वहीं शाह रुख की इस फिल्म से उनकी झलक पाने के लिए फैंस बेताब हैं और अब लीजिए हाल ही में फिल्म से शाह रुख का एक लुक सामने भी आ गया है।

किंग से लीक हुआ लुक

जी हां,फिल्म किंग से शाह रुख खान फिर से पठान और जवान की तरह ही पर्दे पर धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में शाह रुख का ताबड़तोड़ एक्शन होगा,इसकी गवाही हाल ही में सामने आई एक तस्वीर दे रही है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर फिल्म किंग के सेट से लीक हुई है। इस तस्वीर में शाहरुख खान नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में शाह रुख का माचौ अवतार दिखाई दे रहा है। सामने आई तस्वीर एक एक्शन सीन के दौरान की है। जिसमें शाह रुख खान एक गोदाम या फैक्ट्री के सेट के बीचों-बीच खड़े नज़र आ रहे हैं। ब्लैक कपड़ों में शाह रुख के शर्ट के कुछ बटन खुले हुए हैं। बिखरे हुए बाल,बढ़ी हुई दाढ़ी और चेहरे,हाथों पर नकली खून और चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लुक

वहीं तस्वीर में दिख रहा है कि शाह रुख ने एक हाथ में लोहे की रॉड पकड़ी हुई है,वहीं आसपास जमीन पर कई लोग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। शाह रुख का ये जबरदस्त लुक अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद से फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं तस्वीर से एक और बात साफ हो रही है कि फिल्म में एक्शन भरपूर होगा। वहीं फिल्म में शाह रुख के साथ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगीं और फिल्म में दीपिका भी एक्शन करती हुई दिखाई दे सकती हैं। इससे पहले भी दोनों ने पठान में साथ काम किया था और फिल्म में दोनों ने खूब एक्शन किया था।

वहीं किंग में शाह रुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगीं। सुहाना के किरदार के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन बाप-बेटी की जोड़ी को देखने के लिए भी दर्शक उत्साहित हैं। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं फिल्म इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी।

सूर्या ने 2026 में सूर्या 47 की रिलीज की पुष्टि की,हैट्रिक पर नजर

एक्टर सूर्या 2026 को अपने लिए यादगार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं,क्योंकि वे तीन फिल्में रिलीज़ करने वाले हैं। सूर्या ने पहले ही अपनी 46वीं फिल्म करुप्पु रिलीज़ की थी जो ब्लॉकबस्टर रही,और अब एक्टर ने कन्फर्म किया है कि उनकी आने वाली फिल्म-जो उनकी 47 वीं फिल्म है-भी इसी साल के आखिर तक रिलीज़ हो जाएगी। एक बातचीत में, सूर्या ने बताया कि उनके बिना नाम वाले आने वाले प्रोजेक्ट की शूटिंग पूरी हो चुकी है। उनके एंटरटेनमेंट बैनर तले बनी यह फिल्म अभी पोस्ट-प्रोडक्शन प्रोसेस में है और मेकर्स जल्द ही इसका टाइटल और रिलीज डेट बताएंगे। सूर्या 47 के रिलीज़ होने से पहले, सूर्या वेंकी अटलूरी के डायरेक्शन में बनी विश्वनाथ एंड सन्स में नज़र आएंगे। इस फिल्म में ममिता बैजू फीमेल लीड रोल में हैं और यह 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ होने वाली है। सूर्या की इस फिल्म को लेकर पहले ही काफी चर्चा है और यह इस साल के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है। अपनी फिल्म करुप्पु की ज़बरदस्त सफलता के साथ, सूर्या के करियर ने ज़बरदस्त रफ़्तार पकड़ी है। इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनने के बाद एक्टर का करियर शानदार चल रहा है। विश्वनाथ एंड सन्स से जुड़ी अच्छी उम्मीदों और जिथु माधवन की फिल्म के 2026 के आखिर तक रिलीज़ होने की योजना के साथ,एक्टर के पास हैट्रिक लगाने का शानदार मौका है।सूर्या और जिथु माधवन पहले भी साथ काम कर चुके हैं और उनके आने वाले प्रोजेक्ट की काफी चर्चा है, क्योंकि हर कोई इस शानदार डायरेक्टर का जादू देखने के लिए बेताब है।

सोशल मीडिया दबाव पर प्रीति जिंटा की चिंता बोलीं...युवाओं के लिए बढ़ी चुनौतियां

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और इसके कारण युवाओं पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को लेकर अपनी राय रखी है। बंटवारे पर आधारित फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर आयोजित प्रेस बातचीत के दौरान प्रीति जिंटा ने कहा कि मौजूदा दौर में बच्चों और युवाओं के लिए चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। फिल्म से जुड़े कार्यक्रम में प्रीति जिंटा काफी उत्साहित नजर आईं। इस दौरान जब उनसे सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने के चलन और ऑनलाइन दुनिया के बढ़ते प्रभाव के बारे में सवाल किया गया,तो उन्होंने युवाओं की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज का समय युवा पीढ़ी के लिए आसान नहीं है। अभिनेत्री ने तुलना करते हुए बताया कि पहले स्कूल या आसपास के सीमित दायरे में कुछ लोग परेशान करते थे,लेकिन आज इंटरनेट के दौर में आलोचना और नकारात्मकता का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। प्रीति जिंटा ने कहा कि पहले किसी बच्चे को परेशान करने वालों की संख्या सीमित होती थी,लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण लाखों लोग किसी व्यक्ति की जिंदगी में टिप्पणी करने और आलोचना करने की स्थिति में आ सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है और इससे निपटना नई पीढ़ी के लिए बड़ी चुनौती है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया की उपयोगिता को नकारा नहीं, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को अपनी बात रखने का अवसर दिया है, लेकिन इसके साथ ही आलोचना,ट्रोलिंग और ऑनलाइन दबाव जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। आज सोशल मीडिया लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। खासकर युवा वर्ग अपनी पढ़ाई,करियर,मनोरंजन और सामाजिक संपर्क के लिए इन प्लेटफॉर्म का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करता है। ऐसे में ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं का असर उनके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। प्रीति जिंटा ने बातचीत के दौरान यह भी संकेत दिया कि नई पीढ़ी को डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। इंटरनेट पर मिलने वाली हर प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है और लोगों को अपनी वास्तविक पहचान और आत्मविश्वास को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।

अभिनय को लेकर बहुत लालची हूं, जैस्मिन भसीन ने अपने जुनून पर की बात

अभिनेत्री जैस्मिन भसीन इन दिनों एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वह जहां एक तरफ स्टंट-आधारित रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 में खतरनाक टास्क करती नजर आ रही हैं,वहीं दूसरी तरफ अपनी आगामी पंजाबी फिल्म जुदा की रिलीज को लेकर भी उत्साहित हैं। अलग-अलग भाषाओं और प्लेटफॉर्म पर काम करने के अपने अनुभव को लेकर जैस्मिन का कहना है कि अभिनय उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा जुनून है।

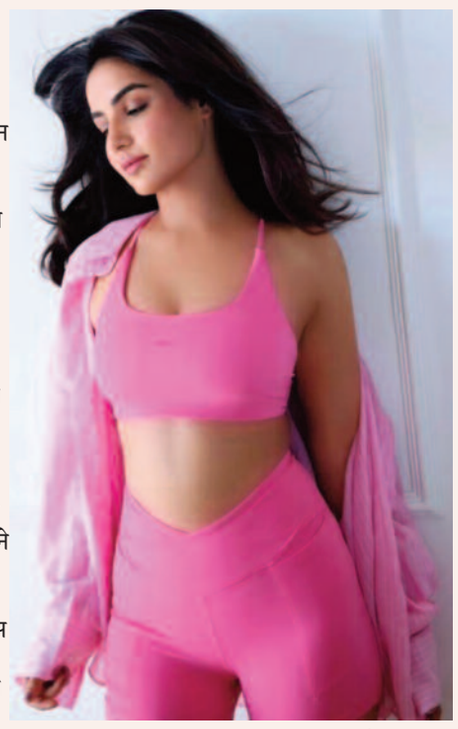

इसलिए वह हर नए मौके को स्वीकार करना चाहती हैं और खुद को अलग-अलग भूमिकाओं में आजमाना चाहती हैं। जैस्मिन भसीन ने अपने करियर और अभिनय के प्रति अपने लगाव को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि अभिनय को लेकर मैं बहुत लालची हूं क्योंकि यह मेरा सबसे बड़ा प्यार और मेरा जुनून है।

मेरे सामने चाहे कुछ भी आए, मैं हमेशा उसे एक्सप्लोर करना चाहती हूं और अपना पूरा योगदान देना चाहती हूं। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि काम किस भाषा या प्लेटफॉर्म पर है, मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मुझे कुछ नया करने और सीखने का मौका मिले। उन्होंने कहा, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत और आभारी महसूस करती हूं कि मुझे अलग-अलग भाषाओं और प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिल रहा है।

अलग-अलग तरह के दर्शकों से जुडना मेरे लिए बहुत खास अनुभव है। अभिनेत्री ने कहा, एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना आसान नहीं होता। यह सफर व्यस्त जरूर है लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरे हर दिन में कोई नई चुनौती हो। एक कलाकार के तौर पर मैं हमेशा खुद को आगे बढ़ाना चाहती हूं और कुछ नया सीखना चाहती हूं।

सुरेंद्र पाल ने महाभारत में प्रदीप रावत के पिता द्रोणाचार्य की भूमिका को याद किया

अनुभवी एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ने महाभारत में अपने साथ काम करने वाले एक्टर प्रदीप राम सिंह रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सुरेंद्र ने मशहूर टीवी सीरीज में साथ बिताए समय को याद किया और गजनी एक्टर द्वारा अश्वत्थामा के यादगार किरदार को निभाने की तारीफ़ की। महाभारत से अपना एक सीन वाला वीडियो शेयर करते हुए, सुरेंद्र ने प्रदीप को श्रद्धांजलि दी और मशहूर टीवी सीरीज़ से जुड़ी अपनी यादगार यादों को ताज़ा किया। उन्होंने लिखा,बहुत जल्दी चले गए, लेकिन कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। महाभारत में प्रदीप रावत जी के साथ काम करना एक ऐसी याद है जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। अश्वत्थामा के तौर पर उनका समर्पण,मज़बूती और दमदार मौजूदगी ने उन्हें देखने वाले हर दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी। कुछ सफ़र खत्म हो जाते हैं,लेकिन सच्चे लेजेंड अपने काम और पीछे छोड़ी गई यादों के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहते हैं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, मेरे दोस्त। ओम शांति। सुरेंद्र पाल सिंह ने बी.आर. चोपड़ा की मशहूर 1988 की टीवी सीरीज़ महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का यादगार किरदार निभाया था, जो कौरवों और पांडवों के शाही गुरु और अश्वत्थामा के पिता थे। प्रदीप रावत ने इस लोकप्रिय पौराणिक शो में द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा का दमदार किरदार निभाया था। उनकी एक्टिंग ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत, जो 1988 से 1990 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी,भारत की सबसे मशहूर पौराणिक टीवी सीरीज़ में से एक है। इस मशहूर शो में कई यादगार परफॉर्मेंस देखने को मिलीं, जिनमें दुर्योधन के तौर पर पुनीत इस्सर,अर्जुन के तौर पर फ़िरोज़ खान और भीष्म के तौर पर मुकेश खन्ना शामिल थे। गजनी और लगान जैसी फ़िल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के बाद, कई मशहूर हस्तियों ने इस अनुभवी एक्टर को श्रद्धांजलि दी। रितेश देशमुख ने शोक व्यक्त किया और दिवंगत स्टार को याद किया। अपनी तस्वीर शेयर करते हुए 'मस्ती' फ़िल्म के एक्टर ने लिखा,मुझे प्रदीप रावत जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला.वे एक सच्चे और नेक इंसान थे और उनकी हंसी बहुत ज़बरदस्त थी। जब भी वे आस-पास होते,तो माहौल हंसी-मज़ाक से भर जाता था। उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

खेल समाचार

श्रीलंका के चार खिलाड़ी जिनसे टीम इंडिया को रहना होगा सचेत

भारतीय टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच गई है...टीम को 15 अगस्त से पहला मैच खेलना है...

कोलंबो,05 अगस्त 2026। श्रीलंका को भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। 15 अगस्त से होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच भी गई है। हालांकि अभी तक श्रीलंका की टीम का ऐलान नहीं हुआ है। टेस्ट में भारत का हालिय प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। टीम रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं श्रीलंका की टीम का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं है। टीम छठे स्थान पर है। हालांकि श्रीलंका के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय इंडिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। हम आपको 4 ऐसे ही नामों के बारे में बताते हैं।

पथुम निसांका

ओपनर पथुम निसांका श्रीलंका के सबसे प्रमुख बल्लेबाज हैं। 19 मैचों के टेस्ट सीरीज में वह 1310 रन बना चुके हैं। उनके नाम 4 शतक भी हैं। भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके बल्ले से शतक भी निकला है। वह खुद को किसी भी परिस्थिति में ढाल सकते हैं।

प्रभात जयसूर्या

भारत को श्रीलंका में टेस्ट मैच जीतना है तो इस गेंदबाज को विकेट नहीं देना होगा। बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात के नाम 23 टेस्ट मैचों में 125 विकेट हैं। वह 12 बार पारी में 5 जबकि दो बार मैच में 10 विकेट ले चुके हैं। श्रीलंका में खेले 14 मैचों में उनके नाम 96 विकेट हैं।

दिनेश चांदीमल

श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप में दिनेश चांदीमल सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। 92 टेस्ट मैचों में वह 16 शतक की मदद से 6530 रन बना चुके हैं। उनका औसत 43.53 का है। भारत के खिलाफ 8 टेस्ट में उनका औसत 50 का है। इसमें 164 रनों की पारी शामिल है। इससे श्रीलंका 2015 में भारत के खिलाफ पहली पारी में 192 रनों से पिछड़ने के बाद भी टेस्ट जीत गया था।

कमिंदु मेंडिस

27 साल के कमिंदु मेंडिस श्रीलंका के लिए काफी भरोसमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। 16 टेस्ट में वह 58 की औसत से 1453 रन बना चुके हैं। इसमें 5 शतक हैं और 6 फिफ्टी हैं। घर में खेले 7 टेस्ट में उनका औसत 64 का है।

ओलंपिक में बिना डर उतरें तो पदक जीतना असंभव नहीं : यामिनी मौर्य

भिवानी,05 अगस्त 2026। भारतीय जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके प्रदर्शन ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि वह दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकती हैं,क्योंकि वह पहले ही ओलंपिक मेडल जीतने वालों और वर्ल्ड चैंपियन का सामना कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस अनुभव से 2028 ओलंपिक का दबाव कम हुआ है और भारत के लिए मेडल जीतने की उनकी उम्मीदों को लेकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। यामिनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में इंग्लैंड की एसिल्या टोपराक के खिलाफ कड़े मुकाबले के बाद सिल्वर मेडल जीता।यामिनी ने बताया, कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन एथलीटों ने हिस्सा लिया,जिनमें वे खिलाड़ी भी शामिल थे जिनका सामना हम पहले वर्ल्ड लेवल पर कर चुके हैं। मैंने ओलंपिक मेडल जीतने वालों

और वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ मुकाबला किया है, और अगर मैं उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती हूं,तो इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब मैं 2028 ओलंपिक में जाऊंगी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वैसा ही दबाव महसूस होगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकती हूं। अगर हम बिना किसी डर या दबाव के ओलंपिक में जाते हैं,तो वहां मेडल जीतना नामुमकिन नहीं लगेगा।

भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम का एलान

टायला व्लामिन्क और डार्सी ब्राउन की वापसी

मेलबर्न ,05 अगस्त 2026। भारत दौरे के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम का एलान कर दिया गया है। 15 सदस्यीय टीम में डार्सी ब्राउन और टायला व्लामिन्क की काफी लंबे वक्त के बाद वापसी हुई है। 27 वर्षीय टायला व्लामिन्क टी20 वर्ल्ड कप के दौरान कंधे में चोट की वजह से टीम से बाहर चल रही थीं। अब वे पूरी तरह से फिट हो गई हैं। टीम इंडिया के खिलाफ वनडे और टी20 में व्लामिन्क शानदार प्रदर्शन करने को बेताब है। वहीं, 23 वर्षीय डार्सी ब्राउन टी20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना पाई थीं। लेकिन भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए में उनको जगह मिली है। उनके अनुभव का युवा खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। बता दें कि तीन हफ्तों के इस टूर में न्यू चंडीगढ़ में तीन टी20, मोहाली में तीन एकदिवसीय मुकाबले और धर्मशाला में चार दिन का मैच शामिल है। वनडे मैचों की कप्तानी ताहलिया विल्सन के कंधों पर रहेगी। टी20 मैचों में कप्तानी की जिम्मेदारी निकोल फाल्टम संभालेंगी, जबकि चार दिवसीय मुकाबले में रेचल ट्रेनमैन कप्तानी करेंगी।

नेशनल सिलेक्टर शॉन फ्लेगलर ने

कहा, दोनों ही ग्रुप में इंटरनेशनल खिलाड़ियों के चयन से हमारे कुछ युवा खिलाड़ियों को उनसे सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। फ्लेगलर ने आगे कहा, खिलाड़ियों के पास सबकॉन्टिनेंटल कंडीशंस में अनुभव लेने और विपक्षी टीम के खिलाफ खुद को परखने का शानदार मौका है। किसी खिलाड़ी के करियर की शुरुआत के लिए भारतीय कंडीशन में खेलना काफी अच्छा होता है। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम- डार्सी ब्राउन, मैटलन ब्राउन, निकोल फाल्टम, टेस फ्लिंटॉफ, सियाना जिंजर, चार्ली नॉट, अनिका लियरॉयड, केटी मैक, लिली मिल्स, फ्रेंकी निकलिन, हेली सिल्वर-होम्स, रेचल ट्रेनमैन, कोर्टनी वेब, ताहलिया विल्सन, और टायला व्लामिन्क।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रभा गुप्ता आ0 गोपाल गुप्ता निवासी देवीगंज,अम्बिकापुर (थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के .अपने पिता स्व0 जगरनाथ साव आ0 सेवक राम की दिनांक 10/01/1975 को स्थान अम्बिकापुर में हुई है। आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है । अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है ।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 31/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

एसए 20 में पहली बार खेलेंगे मिचेल मार्श

फाफ डु प्लेसिस और कीरोन पोलार्ड को किया गया रिलीज

नई दिल्ली,05 अगस्त 2026। दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग एसए 20 का पांचवां सीजन पहले से भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अगले सीजन से पहले फ्रेंचाइजियों ने अपने रिटेंशन और नए साइनिंग्स की घोषणा कर दी है। इसमें मिचेल मार्श,जो रूट,सैम करन,जेसन होल्डर और फिल सॉल्ट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिचेल मार्श पहली बार लीग में खेलते नजर आएंगे। तीन बार की चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। मार्श टीम में क्विंटन डी कॉक,मैथ्यू ब्रीट्जके ,जॉर्डन हरमन और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाज हैं। 17 जनवरी से लीग के नए सीजन की शुरुआत होगी।

सैम करन बने डरबन सुपर जायंट्स का हिस्सा

इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन इस बार डरबन सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगे। वह यहां अपने साथी खिलाड़ी जोस बटलर के साथ नजर आएंगे। करन इससे पहले एसए 20 के शुरुआती दो सीजन में एमआई केप टाउन का हिस्सा थे। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट एक बार फिर पार्ल रॉयल्स की जर्सी में दिखाई देंगे। इससे पहले भी वह टीम के लिए खेल चुके हैं और उन्होंने युवा बल्लेबाज लुआन-ड्रे प्रिटोरियस के साथ शानदार साझेदारियां की थीं। पिछले सीजन की उपविजेता प्रिटोरिया कैपिटल्स ने अपनी बल्लेबाजी को और मजबूत करते हुए फिल सॉल्ट और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैट शॉर्ट को टीम में शामिल किया है। दोनों खिलाड़ी फिलहाल द हंड्रेड में वेल्श फायर के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। टीम में पहले से मौजूद डेवाल्ड ब्रेविस, शेरफेन रदरफोर्ड, आंद्रे रसेल और कॉनर एस्टरहुइजन के साथ कैपिटल्स का बल्लेबाजी क्रम काफी मजबूत नजर आ रहा है। वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर इस बार जॉबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे।

साय कैबिनेट के बड़े फैसले...PWD के काम होंगे ऑनलाइन,500 करोड़ के AI मिशन को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में BEML लगाएगी भारी मशीन बनाने का प्लांट

रायपुर,05 अगस्त 2026। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। मीटिंग में डिजिटल तकनीक,उद्योग,सड़क,वित्त और बिजली से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में 500 करोड़ रुपए के मिशन, [illegible] के भारी मशीन निर्माण संयंत्र,गांवों की सड़क योजना में बदलाव,सरकारी योजनाओं की नई भुगतान व्यवस्था और बिजली कंपनी के लिए 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड समेत 7 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ तेजी आएगी।

लोक निर्माण विभाग के काम अब पूरी तरह होंगे ऑनलाइन

लोक निर्माण विभाग में वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के पहले चरण को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था के तहत काम की मंजूरी, ई-टेंडर,ई-मेजरमेंट बुक,बिल भुगतान,लेखा प्रबंधन और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस सिस्टम के लागू होने से निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बिलों का भुगतान तेजी से होगा और सभी परियोजनाओं की रियल-टाइम निगरानी संभव हो सकेगी।

500 करोड़ के एआई मिशन को मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन अगले 5 साल तक चलाया जाएगा,जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सुशासन को मजबूत करना,नई तकनीक को बढ़ावा देना और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना है। मिशन के तहत राज्य में 100 डेटा लैब स्थापित की जाएंगी। साथ ही 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे,जहां से जुड़ा शोध और प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार 300 से अधिक स्टार्टअप को सहायता देगी,ताकि राज्य में नए तकनीकी कारोबार को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा 6 लाख छात्रों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकारी सेवाओं को अधिक तेज और आसान बनाने के लिए 50 से ज्यादा आधारित सेवाएं भी विकसित की जाएंगी।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड लगाएगी भारी मशीन बनाने का प्लांट

कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए रियायती दर पर जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे राज्य में इस क्षेत्र का पहला उद्योग बताया गया है। सरकार के मुताबिक इस संयंत्र से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी। बड़े निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और MSME सेक्टर को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे राज्य को भारी मशीन निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान मिलने का रास्ता भी खुलेगा।

गांवों में सड़क और नाली बनाना होगा आसान

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत अब गांवों की आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली का निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही,सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी का काम कराने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब उन ग्रामीण सड़कों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या किसी अन्य योजना के दायरे में नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर इन कार्यों के लिए नाबार्ड,खनिज न्यास और अन्य उपलब्ध फंड से भी वित्तीय सहायता ली जा सकेगी।

एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा 15 करोड़ का अनुदान

एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15 करोड़ रुपए का अनुदान (ग्रांट) लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह राशि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता परियोजना पर खर्च की जाएगी। इस परियोजना के तहत सरकारी वित्त व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और जलवायु के अनुकूल विकास परियोजनाएं तैयार की जाएंगी। साथ ही राज्य की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की बेहतर योजना और निगरानी भी की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह अनुदान आधारित परियोजना है,इसलिए इसके लिए राज्य सरकार को कोई वित्तीय योगदान नहीं देना होगा।

सरकारी योजनाओं के पैसे पर होगी बेहतर निगरानी

राज्य में स्टेट सिंगल नोडल एजेंसीमॉडल लागू करने के प्रस्ताव हरी झंडी दे दी गई है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के पैसे का पारदर्शी और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। नई प्रणाली के तहत योजनाओं की राशि एक केंद्रीय खाते में रखी जाएगी। जरूरत होने पर वहीं से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों के खातों में भुगतान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से फंड के दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही योजनाओं के खर्च और क्रियान्वयन की रियल-टाइम निगरानी भी की जा सकेगी, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

बिजली कंपनी जारी करेगी 200 करोड़ के बॉन्ड

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर/बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कंपनी को नए वित्तीय संसाधन जुटाने का अवसर मिलेगा, जिससे बिजली परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा और राज्य के बिजली ढांचे के विकास को गति मिलेगी। कैबिनेट ने बॉन्ड के मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने का भी फैसला लिया है। इससे कंपनी को बाजार से बेहतर शर्तों पर धन जुटाने में आसानी होगी।

रायपुर पहुंची भिलाई बचाओ अभियान पदयात्रा अनुपम गार्डन के पास पुलिस ने रोका

रायपुर,05 अगस्त 2026। भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर निकाली गई 'भिलाई बचाओ अभियान' पदयात्रा बुधवार को राजधानी रायपुर पहुंची। आंदोलनकारी राज्यपाल रमेन डेका को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपने लोकभवन जा रहे थे,लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुपम गार्डन के पास रोक दिया। पदयात्रा का नेतृत्व भिलाई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने किया। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य भिलाई इस्पात संयंत्र,उसके कर्मचारियों,सेवानिवृत्त कर्मियों और टाउनशिप निवासियों से जुड़े लंबित मुद्दों को राज्यपाल के समक्ष उठाना है। कांग्रेस की ओर से जारी अपील में केंद्र सरकार की नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की नीति का विरोध करते हुए आरोप लगाया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों के निजीकरण और भूमि के व्यावसायिक उपयोग की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से बीएसपी और उसकी टाउनशिप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कांग्रेस ने इसे कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के हितों के खिलाफ बताया है। ज्ञापन में बीएसपी एवं पेरिफेरल कर्मचारियों का लंबित वेतन पुनरीक्षण शीघ्र लागू करने, संयंत्र में नियमित भर्ती शुरू करने,सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवास सुविधा बहाल करने तथा सेक्टर-9 अस्पताल के आउटसोर्सिंग और विभागों के निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग की गई है। इसके अलावा टाउनशिप में आवास खाली कराने संबंधी नोटिस वापस लेने, 650 वर्गफुट आवासों का नियमितीकरण करने, बीएसपी स्कूलों को लीज पर देने की प्रक्रिया रोकने, टाउनशिप की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने और बीएसपी की

नियमित भर्तियों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। मुकेश चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण,कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती तथा टाउनशिप से जुड़ी जनविरोधी नीतियों का लगातार विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा करना है।

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाला..अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत,सुनवाई पूरी होने तक छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा

रायपुर,05 अगस्त 2026। शराब घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि,कोर्ट ने जमानत के साथ सख्त शर्त भी लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ट्रायल के दौरान अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही उन्हें अपने रहने का पता और मोबाइल नंबर संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल के दौरान जब भी अदालत बुलाएगी,अनवर ढेबर को पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान अनवर ढेबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा,जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने पैरवी की।

गवाहों को प्रभावित करने की आशंका : इस सुनवाई के दौरान सरकार के पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा कि यदि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए जमानत की शर्त के रूप में उन्हें राज्य से बाहर रहने का निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों को अपना वर्तमान पता और संपर्क नंबर देने के लिए भी कहा गया है। यह मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार,CSMCL में कथित तौर पर एक संगठित तंत्र काम कर रहा था। आरोप है कि मैनपावर सप्लाई एजेंसियों से उनके वैध बिल और बकाया राशि मंजूर कराने के बदले अवैध कमीशन लिया जाता था। यह रकम कथित तौर पर बिचौलियों के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंचाई जाती थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर एजेंसियों का दावा है कि कई एजेंसियों को भुगतान जारी कराने के लिए कथित रूप से कमीशन देने के लिए मजबूर किया जाता था।

इसी मामले में अनवर ढेबर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा अनवर ढेबर शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल हैं। ढेबर को अन्य मामलों में भी आरोपी बनाया गया है। मामले में ED ने कार्रवाई करते हुए अनवर ढेबर से जुड़ी कई संपत्तियों को अटैच किया था। इनमें रायपुर स्थित जमीनें और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। ED का दावा है कि ये संपत्तियां कथित अपराध से अर्जित धन से जुड़ी हुई हैं।

हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दी थी जमानत याचिका

इससे पहले 13 मई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से राज्य सरकार के निगम में गहराई तक फैले एक संगठित भ्रष्टाचार तंत्र का संकेत मिलता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराध सामान्य अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं। ऐसे मामलों में बड़े पैमाने पर जनता के पैसे के नुकसान और सुनियोजित साजिश की आशंका रहती है, जिसका असर व्यापक स्तर पर पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों में जमानत पर विचार करते समय विशेष सावधानी बरतना जरूरी है।

रायपुर रेलवे स्टेशन पर 600 किलो संदिग्ध पनीर जब्त

रायपुर,05 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर लगे प्रतिबंध के बावजूद इसकी अवैध तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त कार्रवाई में पिछले 24 घंटे के भीतर करीब 600 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार,इसमें से 100 किलो पनीर बिना किसी रेलवे बुकिंग के लिंक एक्सप्रेस के जरिए अंबिकापुर भेजने की

तैयारी थी। वहीं,भोपाल से अमरकंटक एक्सप्रेस के जरिए रायपुर पहुंची 500 किलो की एक अन्य संदिग्ध खेप को भी अधिकारियों ने रोककर अपने कब्जे में ले लिया। प्लेटफॉर्म पर रखी पेटियों पर न तो कोई बारकोड था और न ही रेलवे का लेबल,जिससे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्रवाई के दौरान टीम ने कटनी निवासी प्रांशु राय नाम के युवक को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह आशीष जायसवाल नामक व्यक्ति के कहने पर बिना बुकिंग पनीर ट्रेन में चढ़ाने आया था। युवक के मोबाइल की जांच में सौरभ शर्मा और आशीष जायसवाल के साथ पनीर सप्लाई से जुड़ी लंबी बातचीत और चैट रिकॉर्ड मिले हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब्त पनीर के सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भेज दिए हैं।

सांसद बृजमोहन विवाद में उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान,अधिकारियों को दी नसीहत....

रायपुर,05 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और आईएएस अधिकारी अमित कटारिया के बीच हुए विवाद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मामले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका और सम्मान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का विशेष स्थान होता है और प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। उनके अनुसार अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और परिस्थितियों के अनुरूप उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

'जनप्रतिनिधियों का सम्मान प्रशासन की जिम्मेदारी' : मीडिया से बातचीत के दौरान अरुण साव ने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं। ऐसे में संवाद सम्मानजनक होना चाहिए और प्रशासनिक स्तर पर उनकी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल औपचारिकता नहीं,बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

तीन साल से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों के तबादले पर भी बोले : उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तीन वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों के तबादले संबंधी निर्देशों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस विषय पर विभाग पहले से ही स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। यदि किसी विशेष मामले में शिकायत प्राप्त होती है तो सरकार उसका संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगी। उनके अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाए रखने के लिए समय-समय पर ऐसे कदम उठाना जरूरी होता है।

कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार

तबादलों को लेकर कांग्रेस की ओर से की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण साव ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तबादलों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे,उसे इस विषय पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाते हैं। इससे कार्यप्रणाली में सुधार आता है,प्रशासनिक कसावट बढ़ती है और विकास कार्यों को गति मिलती है।

विकास कार्यों में देरी पर सरकार कर रही समीक्षा

नगर निकायों के लिए राशि जारी होने के बावजूद कुछ स्थानों पर विकास कार्यों में देरी के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि जिन योजनाओं में विलंब हो रहा है,उनके कारणों की समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाधाओं की पहचान कर जल्द समाधान निकालें,ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो और जनता को समय पर सुविधाएं मिल सकें।

दो भाई लगातार मंदिरों में कर रहे थे चोरी,जांजगीर पुलिस का खुलासा

जांजगीर चांपा,05 अगस्त 2026। जिले में मंदिरों में चोरी की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। लाखों का कर्ज चुकाने के लिए नाबालिग समेत 4 चोरों ने तीन मंदिरों को निशाना बनाया। वारदात के बाद चोरी का सारा माल जमीन के नीचे गाड़ दिया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले का खुलासा एसपी विजय पाण्डेय ने किया है। चोर गैंग ने 1 से 2 अगस्त की दरमियानी रात तीन मंदिरों को धावा बोला।

बम्हनीडीह के रामजानकी मंदिर में घुसकर चोरों ने चांदी के 2 छत्र पार कर दिया। नवागढ़ थाना क्षेत्र के महंत गांव के चंडी दाई मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। यहां 9 माताओं के सिर पर सजी चांदी के मुकुट, सोने के जेवर की चोरी की। वह दान पेटी भी अपने साथ ले गए। वहीं जगमहंत के बद्री विशाल मंदिर में चोरों ने चांदी का छत्र पर हाथ साफ किया। इन घटनाओं के बाद लोगों में भारी आक्रोश था। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तीनों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में जुट गई। चोरी की घटनाओं की जांच के लिए पुलिस ने टीम गठित की। घटनास्थल की निरीक्षण करने के बाद करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक पर 4 संदिग्ध लोग सवार दिखे। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को दबोचा।

पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया उनपर लाखों रुपए का उधार था, जिसे चुकाने के लिए घटना को अंजाम दिया। साथ ही पुलिस को चोरी के माल को छिपाए गए अड्डे की जानकारी दी।

कांग्रेस नेता मर्डर केस...3 नाबालिग समेत 4 आरोपी अरेस्ट

रास्ता पूछा तो लूटने पीछा किया,सुनसान जगह देखकर हमला,राहगीरों को बनाते थे निशाना

दुर्ग-भिलाई,05 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांग्रेस के मंडल कोषाध्यक्ष प्रकाश सिंह कश्यप की हत्या मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। जांच में सामने आया है कि वारदात से कुछ देर पहले कांग्रेस नेता और उनके साथियों ने रास्ता पूछने के लिए बाइक सवार युवकों को रोका था। आरोपियों ने रास्ता बताने के बाद उनका पीछा शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें दुर्ग-धमधा रोड पर सुनसान जगह मिली, उन्होंने डंडा अड़ाकर बाइक रुकवाई और लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर प्रकाश सिंह कश्यप पर धारदार हथियार से कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोपी मोबाइल और कैश लेकर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक 2 अगस्त की रात तुमाकला के रहने वाले चोवाराम लोधी अपने परिचित भूषण पटेल और प्रकाश सिंह कश्यप के साथ जुनवानी के अस्पताल से वापस घर की ओर जा रहे थे। आगे जाकर रास्ता भटकने पर उन्होंने एक बाइक पर सवार 4 युवकों से पता पूछा। आरोपियों ने उन्हें रास्ता बता दिया, लेकिन इसके बाद उनकी बाइक के पीछे लग गए। आगे आरोपियों ने बाइक सवारों को रोककर लूट के नीयत से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल प्रकाश सिंह कश्यप को जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चौकी जेवरा सिरसा पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी देर रात सुनसान सड़क पर राहगीरों को निशाना बनाकर लूटपाट करते थे। मामले में पुलिस ने कादम्बरी नगर,मोहन नगर निवासी 19 वर्षीय आदर्श उर्फ लाल को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा तीन नाबालिगों को भी पकड़ा गया है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)